।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

● वर्ष-5
● अंक-226
रायपुर, शनिवार
09 मई 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

पेज-8› बूथ से लेकर जिला तक कार्ययोजना...

सुवेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे

विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने किया एलान, आज लेंगे शपथ

नई दिल्ली। कोलकाता, 08 मई (वार्ता) पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता सुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं स्वामी प्रणबानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा बंगाल के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया।

श्री अधिकारी ने पार्टी विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंगाल की जनता का भाजपा पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह जनादेश राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव चाहने वाले लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

उन्होंने पिछले कई वर्षों में बंगाल में पार्टी के सांगठनिक संघर्षों को याद करते हुए, उन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदानों को याद किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक आंदोलनों और झड़पों के दौरान कथित तौर पर उनकी जान चली गयी थी। बंगाल में पार्टी के विस्तार के दौरान हजारों भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं को हिंसा, उत्पीड़न और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं के बलिदान और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। उनके सपने और आकांक्षाएं अब सुशासन और विकास के माध्यम से पूरी होंगी। भाजपा की शासन प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि नयी सरकार ज़्यादा काम और कम बातों पर ध्यान देगी। साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी। महिलाओं की सुरक्षा और हिफ़ाज़त सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। संदेशखाली जैसी घटनाओं और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ी कथित अनियमितताओं का ज़िक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि इन मामलों की जाँच के लिए जाँच आयोग गठित किए जाएँगे। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, जो भी लोग दोषी पाए जाएँगे, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलग-अलग क्षेत्रों में संस्थागत भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों की जाँच के लिए गठित आयोगों की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

मुख्य मेहमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: शपथ समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। मोदी बंगाल में कई बार रैलियां कर चुके हैं। उनकी मौजूदगी केंद्रीय समर्थन का संदेश देगी। अमित शाह- 8 मई को ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा-अर्चना की। यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है - बंगाल की आस्था को सम्मान देना। भाजपा अध्यक्ष- पूर्ण सत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री- भाजपा शासित राज्य जैसे - योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), मोहन यादव (मध्य प्रदेश), भूपेंद्र पटेल (गुजरात), देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र), हिमंता बिस्वा सरमा (असम), मनोहर लाल खट्टर/नायब सिंह सैनी (हरियाणा), भजन लाल शर्मा (राजस्थान), मोहन चरण मांझी (ओडिशा), पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड) आदि। साथ में हृष्ठ सहयोगी ष्टरू भी। कुल 20 सीएमएस की लिस्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा आदि शामिल।

जादुई आंकड़ा किया पार, एक्टर विजय आज बनेंगे मुख्यमंत्री

चेन्नई। तमिलनाडु में शुक्रवार को दिनभर चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अभिनेता सी. जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव में श्री विजय की पार्टी 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ पीछे रह गयी, जिसके कारण राज्य में अनिश्चितता का एक दौर शुरू हो गया था।

विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची (वीसीके), दोनों वामपंथी दलों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने कांग्रेस की राह पर चलते हुए अभिनेता सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) को अपना समर्थन दे दिया है, जिससे श्री विजय के पास बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से अधिक संख्या बल जुट गया है।

इसके साथ ही श्री विजय अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल विश्वनाथ राजेंद्र अर्लेकर द्वारा बहुमत का प्रमाण मांगे जाने के बाद, श्री विजय ने कांग्रेस

(5 विधायक), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (2), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (2), वीसीके (2) और आईयूएमएल (2) के समर्थन पत्रों के साथ तीसरी बार राजभवन का दौरा किया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब उनके पास कुल 120 विधायकों का समर्थन है, जो 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 118 से दो अधिक है। इससे पहले राज्यपाल ने स्थिर सरकार के लिए बहुमत के ठोस सबूत की कमी का हवाला देते हुए श्री विजय के दावे को खारिज कर दिया था, जिसकी राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों ने काफी आलोचना की थी। अब टीवीके के पास बहुमत से अधिक संख्या बल होने पर पार्टी के पनैयुर स्थित मुख्यालय और पूरे राज्य में समर्थक आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर इस सफलता का जश्न मना रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस ने परिणाम आने के अगले ही दिन द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) से नाता तोड़कर श्री विजय को समर्थन दे दिया था। अब अन्य सहयोगियों के जुड़ने से रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। हालांकि, वामपंथी दलों ने स्पष्ट किया है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे और उनका समर्थन केवल राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति को रोकने के लिए है। वहीं, चर्चा है कि वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन सांसद पद से इस्तीफा देकर विजय सरकार में उप-मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो सकते हैं।

राजभवन से लौटने के बाद श्री विजय ने व्यक्तिगत रूप से भाकपा और माकपा के कार्यालयों का दौरा कर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने भाकपा कार्यालय में दिवंगत दिग्गज नेता आर. नल्लकन्नु को पुष्पांजलि भी अर्पित की। दिलचस्प बात यह है कि श्री विजय की सुरक्षा, जिसे एक दिन पहले हटा लिया गया था, राजभवन दौरे के साथ ही बहाल कर दी गई है, जो राज्य में बदलती राजनीतिक हवा का स्पष्ट संकेत है।

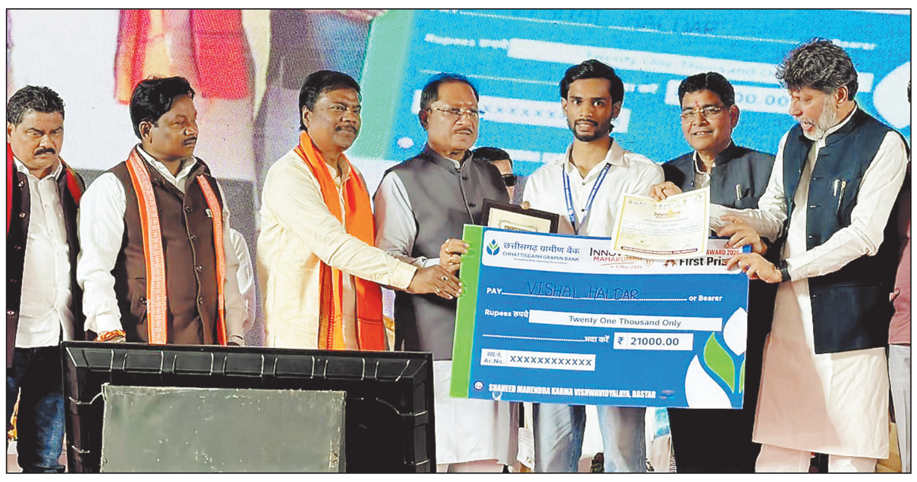

रायपुर। बस्तर के नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध संसाधनों के बीच अब एक नई और सुगंधित क्रांति आकार ले रही है, जिसका श्रेय दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी युवा उद्यमी विशाल हालदार को जाता है। बीकॉम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा प्राप्त करने वाले विशाल ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने और कुछ नया करने की चाह में छिंद के उन बीजों से हर्बल कॉफी तैयार की है, जिन्हें अब तक बस्तर में पूरी तरह व्यर्थ समझा जाता था।

बंगाल में घुसपैठ-गौ तस्करी होगा खत्मः अमित शाह

कोलकाता। कोलकाता में भाजपा की जीत के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें उनके ही घर में हराया है। उन्होंने बंगाल में घुसपैठ और हिंसा खत्म कर सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया और शुभेंदु को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताया।

कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने कहा कि मैं आप सभी को, जिनमें बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हिंसा और धमकियों की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, मैं बंगाल की

जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कम्युनिस्ट युग से चले आ रहे माहौल को ममता बनर्जी ने और भी गहरा कर दिया था, जिसके चलते वहाँ मतदान करना लगभग असंभव हो गया था। बंगाल की जनता ने भाजपा और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताकर जो भारी जीत दिलाई है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।शाह ने कहा कि मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हम पर जो उम्मीदें रखी हैं, जिनके आधार पर उन्होंने हमें यह जनादेश दिया है, हम उस भरोसे को पूरी तरह से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बंगाल की लोकतांत्रिक संरचना में बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच दशकों से बंगाल लोकतंत्र के क्षरण, कानून-व्यवस्था के पतन, अर्थव्यवस्था की दुर्बलता और विकास की धीमी गति से जूझ रहा है। आज बंगाल एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है।

अमित शाह ने कहा कि आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और अब बंगाल में भी हमारी सरकार बनी है... घसपैठ और गौ तस्करी असंभव होने वाली है। दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले की तरह परिवर्तित कर देगी। उन्होंने कहा कि हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि हम सोनार बांग्ला के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें। आज कवि गुरु की ये पंक्तियाँ सत्य सिद्ध हो रही हैं- एक ऐसे बंगाल का मार्ग प्रशस्त हो चुका है जहाँ मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, और बंगाल उस मार्ग पर चल रहा है।शाह ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 हटा तो देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कसर बाकी है।

प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी पहली बार करेंगे टिहरी का दौरा

टिहरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार उत्तराखंड के टिहरी जिले के दौरे पर पहुंच सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मई के अंतिम सप्ताह अथवा जून के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री टिहरी पहुंचकर देश की महत्वपूर्ण 1000 मेगावाट क्षमता वाली टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस संभावित दौरे को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक से अधिक विकास और ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा। टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में माना जा रहा है। यह परियोजना बिजली उत्पादन के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण और राष्ट्रीय ग्रिड संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञ इसे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से गेमचेंजर मान रहे हैं। इसके अलावा श्री मोदी इस दौरान टिहरी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख सकते हैं तथा क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई अन्य योजनाओं की घोषणाएं होने की भी संभावना है।

युद्ध में आश्चर्य का तत्व विकसित करें कमांडरः राजनाथ

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजी से बदलते भू-राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्य में हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा विश्लेषण और सुरक्षित संचार नेटवर्क में क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि भविष्य के संघर्ष हाइब्रिड खतरों, सूचना प्रभुत्व तथा साइबर, अंतरिक्ष और विद्युतचुंबकीय क्षेत्रों में एक साथ संचालित अभियानों से प्रभावित होंगे। श्री सिंह ने संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन कमांडरों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए की त्वरित , सटीक और संयुक्त जवाबी कार्रवाई का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नयी सोच और बेहतर समन्वय से जीते जायेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारतीय रक्षा बलों की त्वरित, सटीक और संयुक्त प्रतिक्रिया का प्रमाण है। उन्होंने तीनों सेनाओं के कमांडरों से आह्वान किया कि वे इस अभियान तथा वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य से सीख लेकर भविष्य के लिए सदैव तैयार रहें।

अमेरिका-ईरान युद्धविराम बरकरारः ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि गुरुवार देर रात अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद भी युद्धविराम बरकरार है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पहले गोली किसने चलाई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के शीर्ष सैन्य कमान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर आ रहे एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य पोत को निशाना बनाया और कई तटीय क्षेत्रों परहवाई हमले किए। इस बीच अमेरिका ने कहा कि उसने जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों पर ईरानी हमलों का जवाब आत्मरक्षा के तौर पर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने शुरू में होर्मुज जलडमरूमध्य में विस्फोटों की सूचना दी, जिसे शत्रुता के साथ गोलीबारी बताया गया। इसके कुछ ही समय बाद, ईरान के शीर्ष सैन्य कमान के एक बयान में कहा गया कि अमेरिकी हवाई हमलों ने बंदर खमीर, सिरिक और केशम द्वीप के तटों को निशाना बनाया।

तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका पर चिदंबरम ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। तमिलनाडु की नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि वह सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। यह केवल राजनीतिक परंपरा ही नहीं, बल्कि संसदीय व्यवस्था का स्थापित नियम भी है। उन्होंने लिखा कि निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़े दल के नेता को पहले सरकार गठन का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद वह विधानसभा में बहुमत साबित कर सकता है। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के 1994 के ऐतिहासिक फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधानसभा को ही बहुमत परीक्षण का सही मंच माना है।

स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली टारा का सफल परीक्षण

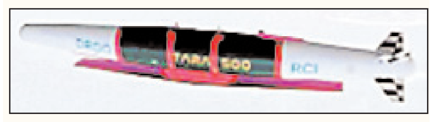

नईदिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना ने पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (टारा) का सफल परीक्षण किया है।रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यह परीक्षण गुरुवार को ओडिशा तट के पास किया गया । टारा, एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो बिना मार्गदर्शन वाले वारहेड को सटीक निर्देशित हथियार में परिवर्तित करती है। टारा को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत तथा डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, ताकि कम लागत वाले हथियार की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ाकर भूमि आधारित लक्ष्यों को निष्क्रिय किया जा सके।

बंगाल में निर्ममता की हार, तुष्टिकरण पर प्रहार और विकास की बयार

प्रेम शुक्ल

पश्चिम बंगाल के जनादेश ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णायक, प्रभावी और परिणाम देने वाले नेतृत्व पर अडिग विश्वास रखती है। यह भरोसा किसी भावनात्मक लहर का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से दिख रहे सुशासन, पारदर्शिता और निरंतर विकास की ठोस बुनियाद पर खड़ा है। यह केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि बंगाल की जनता के भीतर वर्षों से पनप रहे आक्रोश, पीड़ा और बदलाव की आकांक्षा का सशक्त विस्फोट है। इस जनादेश में साफ दिखता है कि जनता ने भय की राजनीति को नकारते हुए भरोसे को अपनाया, तुष्टिकरण को ठुकराकर विकास को चुना और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर सुशासन को प्राथमिकता दी। बंगाल में यह जीत वास्तव में जनता की जीत है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहे टोलाबाजी, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और खुले तुष्टिकरण के खिलाफ जनता लंबे समय से सड़कों पर थी। हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, युवा हो, महिला हो या व्यापारी, सबने इस व्यवस्था के खिलाफ मन बना लिया था। पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिन्दू समाज के साथ

भेदभाव हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति ने सामाजिक संतुलन को बिगाड़ा और अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहन देकर राज्य की पहचान और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए गए। हालात ऐसे बन गए थे कि कई इलाकों में हिन्दू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। चुनाव के समय उन्हें वोट डालने तक से रोका गया, डराया-धमकाया गया। यह लोकतंत्र का अपमान था, लेकिन इस बार जनता ने इन सबका जवाब दिया है। ममता बनर्जी की हताशा चुनाव से पहले ही दिखने लगी थी। एक भ्रष्ट निजी कंपनी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना, मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति का विरोध करना, ये सभी कदम इस बात के संकेत थे कि उन्हें अपनी हार का अंदाजा हो चुका था। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है और जनता ने अपना फैसला स्पष्ट रूप से सुना दिया।

यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखती है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र में भाजपा की सरकार ने जिस तरह से विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया है, उसका असर हर राज्य में दिख रहा है। जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां न केवल विकास हुआ है बल्कि जनता ने बार-बार उस पर मुहर लगाई है। असम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना और वह भी पहले से अधिक, लगभग तीन-चौथाई बहुमत के साथ, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। असम में बुनियादी ढांचे से लेकर कानून-व्यवस्था तक हर क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिसका परिणाम जनता के विश्वास के रूप में सामने आया है।

इन विधानसभा चुनावों में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। राहुल गांधी एक बार फिर इस चुनाव में असफल नेता के रूप में सामने आए हैं। वह न तो इंडी गठबंधन को एकजुट रख पाए और न ही जनता के बीच कोई विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत कर पाए। चुनाव परिणामों के समय उनका विदेश में होना यह दर्शाता है कि वह इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इंडी गठबंधन अब केवल नाम का गठबंधन रह गया है, जिसका भविष्य अंधकारमय दिखता है। तमिलनाडु में वर्षों से जो लोग सनातन संस्कृति का अपमान करते आए, जिन्होंने हिन्दू आस्थाओं को निशाना बनाया, दीपम जैसे धार्मिक आयोजनों में बाधाएं डालीं और धर्म-भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की। जनता ने उन्हें भी करारा जवाब दिया है। सनातन संस्कृति की तुलना डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से करने वाली मानसिकता को जनता ने नकार दिया है। यह बदलाव धीरे-धीरे ही सही, लेकिन स्थायी रूप से उभर रहा है। पुडुचेरी में भी भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है।

समाचार पचीसा
रायपुर, शनिवार 09 मई 2026

8614 उपभोक्ताओं को मिलेगी निर्बाध बिजली

■ दो करोड़ का नया 33/11 KV उपकेन्द्र बनेगा

कबीरधाम। कवर्धा शहर की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नवीन बस स्टैंड घोठिया में 33/11 KV विद्युत उपकेंद्र निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। यह उपकेंद्र लगभग 2.06 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत बनेगा। स्थानीय विधायक व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस परियोजना की सौगात दी।

उन्होंने कहा कि यह केंद्र शहर की विद्युत व्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा। इससे आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। मेडिकल कॉलेज, नवीन बस स्टैंड, कृषि कॉलेज, तुलसी नगर और राजदीप कॉलोनी जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा। शहर के 8614 उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सरकार बनने के बाद ढाई वर्षों में जिले में विद्युत अधोसंरचना मजबूत करने के लिए कार्य हुए हैं। अब तक चार नए उपकेंद्रों का भूमिपूजन पूरा हो चुका है। दलदली, सेमो और सरेखा में पहले ही उपकेंद्रों का भूमिपूजन हो चुका है। जल्द ही दुबहा में भी नए उपकेंद्र का भूमिपूजन किया जाएगा।नवीन उपकेंद्र में 5 रूङ्क क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। यहां से तीन नए 11 चङ्क फीडर निकाले जाएंगे। इनमें मेडिकल कॉलेज फीडर, तुलसीनगर फीडर और राजदीप कॉलोनी फीडर शामिल हैं। इन फीडरों से नव निर्मित मेडिकल कॉलेज, नवीन बस स्टैंड और कृषि कॉलेज को लाभ मिलेगा। तुलसीनगर व राजदीप कॉलोनी क्षेत्र में भी बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।इस नए उपकेंद्र के प्रारंभ होने से लोहारा नाका स्थित उपकेंद्र का भार कम होगा। दशरंगपुर, टाउन-1 और रामनगर फीडरों पर दबाव घटेगा। 11 चङ्क फीडरों की लंबाई घटने से अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति संभव हो सकेगी। इससे आम नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। शहर के कई क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या से भी राहत मिलेगी।

महामाया पहाड़ पर वन विभाग का बुलडोजर चला

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर से लगे महामाया पहाड़ स्थित रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ डबरीपानी क्षेत्र पहुंची। यहां अवैध रूप से बने मकानों को ढहाया गया। वन विभाग के अनुसार, महामाया पहाड़ के कक्ष क्रमांक 2581 और 2582 में अवैध कब्जों को हटाने के लिए मार्च 2026 में 157 लोगों को अंतिम बेदखली नोटिस जारी किया गया था। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने आरोप लगाया कि नोटिस अवधि 27 मार्च को समाप्त होने के बाद भी कार्रवाई में देरी हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत के मार्गदर्शन में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज की। गुरुवार रात वन विभाग की टीम ने डबरीपानी क्षेत्र में पहुंचकर मकान खाली करने की घोषणा की। संबंधित नोटिस भी चस्पा किए गए। अगले ही दिन शुक्रवार सुबह फॉरेस्ट एसडीओ श्वेता कम्बोज के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हुई। इसमें 20 अवैध निर्माण हटाए गए। पार्षद आलोक दुबे ने वन विभाग पर अंतिम बेदखली नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर दूसरे राज्यों से आए समुदाय विशेष के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद ही प्रशासन हरकत में आया। अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। फॉरेस्ट एसडीओ श्वेता कम्बोज ने बताया कि चिन्हित 157 अतिक्रमणकारियों में कुछ लोगों को हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिला है। उनके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंह देव ने कहा कि गैर कानूनी कब्जे पर बेदखली की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भूमाफियाओं के साथ मिलकर कब्जा बेचने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों ने 2-2 लाख रुपये तक लेकर कब्जा बेचा है

भोपालपटनम में बांस कला का संकट, पुश्तैनी हुनर पर मंडराया विलुप्ति का खतरा

बीजापुर। कभी बांस शिल्प कला के लिए पहचान रखने वाला भोपालपटनम क्षेत्र आज अपनी ही पारंपरिक विरासत को बचाने की जंग लड़ रहा है। जिन हाथों ने दशकों तक बांस से तुकनी, सुपा, मुर्गी गुड़ा और घरेलू उपयोग की सामग्री बनाकर गांव-गांव पहचान बनाई, वे हाथ अब रोजी-रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। बाजार में प्लास्टिक और मशीन निर्मित सामानों की बढ़ती मांग ने पुश्तैनी बांस कला को लगभग हाशिए पर पहुंचा दिया है। भोपालपटनम ब्लॉक के गुल्लागुड़ा, मद्देड़ और रुद्राराम गांवों में बसे बुरुड़ समाज के परिवार पिछले करीब एक सदी से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि तत्कालीन जमींदारों ने महाराष्ट्र के आंकिसा गांव से इन परिवारों को यहां बसाया था ताकि स्थानीय जरूरतों के लिए बांस से घरेलू सामग्री तैयार की जा सके। उस समय इनकी कला गांवों की जरूरत थी, लेकिन अब यही हुनर बाजार के अभाव में दम तोड़ रहा है। 70 वर्षीय कोनम जगैया बताते हैं कि उन्होंने 55 वर्षों तक बांस शिल्प के सहारे परिवार चलाया। इसी काम से बच्चों का पालन-पोषण और बेटियों की शादी हुई, लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं कि तैयार सामान घरों में ही पड़ा रह जाता है। उम्र ढल चुकी है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, फिर भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है क्योंकि परिवार के पास न खेती है और न कोई दूसरा सहारा। प्ररला श्रीनिवास और उनकी पत्नी महेश्वरी भी इसी संकट से गुजर रहे हैं। महेश्वरी दिनभर मेहनत कर सुपा और टुकनी तैयार करती हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिलने से मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उनका कहना है कि मेहनत के मुकाबले आमदनी इतनी कम है कि अब यह काम छोड़ने की नौबत आ गई है। सबसे ज्यादा चिंता नई पीढ़ी को लेकर है। गांव के युवा कोनम राजेंद्र बताते हैं कि वे इस कला को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बाजार और सरकारी सहयोग के अभाव में अब मजदूरी और छोटे-मोटे व्यवसाय की ओर जाना पड़ रहा है। उन्होंने बैंक से ऋण लेकर छोटी दुकान शुरू की है।

गोंड समाज के आंदोलन से सड़क पर लगा 3 घंटे से जाम

■ धमधागढ़ के प्रधान कार्यालय और कचना धुरवा देवालय में तालाबंदी के खिलाफ आदिवासी

दुर्ग। केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के बैनर तले गुरुवार को आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के हजारों लोग दोपहर बाद शहर पहुंचे और पटेल चौक पर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गोंड समाज के प्रदर्शन के चलते पटेल चौक समेत आसपास के प्रमुख मार्गों पर करीब तीन घंटे तक लंबा जाम लगा रहा।

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई और लोगों को वैकल्पिक रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। समाज के नेताओं के मुताबिक प्रदर्शन का कारण केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के प्रधान कार्यालय और कचना धुरवा देवालय में लगी तालाबंदी है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में भवन को बंद कराया और निर्वाचित पदाधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं सौंपी। गोंड समाज के सदस्य तारकेश्वर सिंह मरकाम ने बताया कि 12 अक्टूबर 2025 को हुए केंद्रीय गोंड महासभा चुनाव में कमलेश सोरी विजय हुए और एमडी ठाकुर पराजित हुए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी पुराने अध्यक्ष कमलेश सोरी को उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं। चुनाव को लेकर विवाद के बाद मामला फर्म्स एवं सोसायटी विभाग तक पहुंचा, लेकिन 8 मार्च 2026 को आयोजित विशेष सभा में चुनाव परिणाम को वैध मानते हुए नई कार्यकारिणी को वर्ष 2030 तक मान्यता दे दी गई।

आरटीई एडमिशन पर हाईकोर्ट सख्त

■ 387 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं आने पर जताई नाराजगी, सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र में पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर तलब की है। सरकार को बताना होगा कि किस स्कूल में कितनी सीटों पर और किस बच्चे का एडमिशन हुआ है। हाईकोर्ट राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र से नाराज भी हुआ। इसमें सरकार ने बताया है कि राज्य के 387 स्कूलों में एडमिशन के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। वहीं 366 ऐसे स्कूल हैं, जिसमें कुल सीटों के मुकाबले आवेदन काफी कम रहे हैं। इसमें प्रदेश के सभी बड़े स्कूल शामिल है। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई है। साथ ही आश्चर्य भी जताया है कि क्या बड़े स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर राज्य सरकार कुछ छिपा रही है। कोर्ट ने आबंटित सीटों को ऑनलाइन भी करने कहा है।

50 लाख का गांजा जब्त, 5 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस में छिपाकर ले जा रहे 77 किलो अवैध गांजा को जब्त किया है। मामले में महाराष्ट्र के 5 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त एंबुलेंस, पायलेटिंग कार और 5 मोबाइल फोन समेत कुल 50 लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के अनुसार, ओडिशा से महासमुंद की ओर एक एंबुलेंस वाहन क्रमांक एमएच 13 सीयू 0707 में गांजा तस्करी की सूचना मिली थी।

सूचना के आधार पर टेमरी जांच नाका में घेराबंदी कर एंबुलेंस और उसके आगे चल रही पायलेटिंग कार क्रमांक एमएच 12 एनबी 5277 को रोका गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एंबुलेंस में गांजा होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें करीब 77 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 68/2026 के तहत धारा 20(बी)(II)(सी) और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी गांजा को ओडिशा के बालीगुडा क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर में खपाने की तैयारी में थे। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनका प्लान विफल हो गया।

जान बचाने बच्चों संग तालाब में कूदीं महिलाएं

बालोद। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम जगतरा में शुक्रवार को तेंदुए के रेस्क्यू के दौरान अफरा तफरी मच गई। दरअसल, कुएं में गिरे तेंदुए को बाहर निकालने के लिए बुलाई गई जेसीबी जैसे ही उसे ऊपर लाई, तेंदुआ वन विभाग के जाल में फंसने के बजाय सीधे भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए तालाब किनारे खड़ी महिलाओं ने अपने मासूम बच्चों के साथ गहरे पानी में छलांग लगा दी। जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जगतरा के एक कुएं में तेंदुआ गिरने की खबर से सुबह से ही हड़कंप मचा था। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब पिंजरा काम नहीं आया, तो जेसीबी की मदद ली गई। लेकिन जैसे ही तेंदुआ जमीन पर आया, वह बेकाबू होकर भागने लगा। तेंदुए को अपनी ओर आता देख गांव में भगदड़ मच गई। सबसे डरावनी स्थिति तालाब के पास बनी, जहां मौजूद महिलाएं और बच्चे तेंदुए के सीधे निशाने पर आ गए थे। तेंदुए के पंजों से बचने के लिए महिलाओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके चलते उन्होंने बच्चों सहित तालाब में छलांग लगा दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो दिल दहला देने वाला है। तेंदुआ वर्तमान में गांव के रिहायशी इलाके या आसपास के खेतों में कहीं छिपा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग अपनी छतों पर बैठकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पुलिस और वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ से बाहर है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नौकरी का झांसा देकर झारखंड में 35 युवती को बनाया बंधक

जगदलपुर। कांकेर जिले के दुर्गकोंदल में रहने वाली दुर्गकोंदल की 35 युवतियों को नौकरी देने के नाम पर झारखंड में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया, बंधक युवतियों में से एक युवती ने अपने साथ हुए घटना की जानकारी मैसेज के माध्यम से गांव के युवक को भेजा। जिसके बाद से गांव में माहौल गरमा गया है। युवतियों को छुड़ाने के लिए कवायद शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नौकरी के नाम पर मानव तस्करी का बड़ा खुलासा सामने आया है। जहां छत्तीसगढ़ की करीब 35 युवतियों को झारखंड में बंधक बना लिया गया है। इस बंधक में दुर्गूकोंदल क्षेत्र की भी कई लड़कियां शामिल हैं। गांव के युवक ने बताया कि दुर्गूकोंदल की युवती के मैसेज से इस बात का खुलासा हुआ है। युवती ने गांव युवक को मैसेज करते हुए मदद की गुहार लगाते हुए संदेश भेजा है। युवती ने अपने मैसेज में कहा कि नौकरी के बहाने ले जाकर जबरन रोक कर रखा गया है। ना तो पैसा दिया जा रहा है और न ही घर जाने की अनुमति मिल रही है।

एमसीबी जिले में कलेक्टर ने जारी की नई अधिसूचना

एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3(बी) के अंतर्गत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन दरों की अधिसूचना जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार यह नई वेतन दरें 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रभावशील रहेंगी। अधिसूचना में मासिक एवं दैनिक वेतन के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कृषि नियोजन तथा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों एवं जोन के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। श्रमिकों का वर्गीकरण अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणियों में किया गया है। कृषि नियोजन के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 6900 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसमें 2450 रुपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़कर कुल मासिक वेतन 9350 रुपये तय किया गया है।

प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के वारिसों को आर्थिक सहायता राशि

कोण्डागांव। कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा पीड़ित के 06 प्रकरण में वारिसों को 24 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा बड़ेराजपुर तहसील के खलारी निवासी अघनसिंह की गाज गिरने से मृत्यु होने पर पत्नी लीलाबाई को, धनोरा तहसील के ग्राम तोड़ासी निवासी रतन की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी सुगन्तीन को, फरसगांव तहसील के ग्राम बड़गई निवासी घस्सू की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी मनाय, पुत्र अस्सीराम को, कोण्डागांव तहसील के ग्राम बाखरा निवासी मनकी बाई विश्वकर्मा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर पति रामसाय विश्वकर्मा को, मर्दापाल तहसील के ग्राम मोहलई निवासी सरादू की सर्पदंश से मृत्यु होने पर पत्नी चमेली को, कोण्डागांव तहसील के ग्राम सुकुरपाल निवासी गुनगुन कश्यप की सर्पदंश से मृत्यु होने पर माता अंजली कश्यप, पिता मानसिंह कश्यप को 04-04 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति प्रदान की गई है।

दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने बस्तर आरटीओ ने जारी किए कड़े निर्देश

जगदलपुर। बस्तर संभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मंशा के अनुरूप अब हाईवे सहित सभी प्रमुख मार्गों पर मोटरसाइकिल चालक के साथ-साथ पीछे बैठे सवार के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 194(घ) के तहत भारी अर्थदंड वसूलने की चेतावनी दी गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में विशेष रूप से उन शोरूम संचालकों को आगाह किया गया है जो पूर्व में जारी आदेशों की अवहेलना करते हुए बगैर हेलमेट के वाहनों की डिलीवरी कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 34 से 44 और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 213 के तहत यह अनिवार्य है कि वाहन की डिलीवरी के समय सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। यदि कोई शोरूम संचालक बिना हेलमेट वाहन सौंपता है।

सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर बस्तर में प्लेसमेंट कैंप

बस्तर। जिला कौशल विकास प्राधिकरण बस्तर ने सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए विशेष प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया है। खास बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया सभी ब्लॉक में होगी। इस भर्ती अभियान की शुरुआत 11 मई को जनपद पंचायत बस्तर से होगी। 12 मई को तोकापाल, 13 मई को लोहण्डीगुड़ा। 14 मई को बास्तानार जनपद पंचायत में रजिस्ट्रेशन। 18 मई को दरभा जनपद पंचायत में शिविर। 19 मई को जगदलपुर स्थित लाईवलीहुड कॉलेज में युवाओं की स्क्रीनिंग। 20 मई को जनपद पंचायत बकावण्ड में आखिरी शिविर। सभी स्थानों पर चयन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक चलेगी।जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि शिविर के लिए सभी ब्लॉक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और पहचान पत्र साथ लाना होगा। वहीं 11 मई को बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए मेगा प्लेसमेंट कैंप भी लगाया जा रहा है।

सांसद चिंतामणि महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बनाई झालमुरी

रामानुजगंज दौरे पर पहुंचे सांसद चिंतामणि महाराज ने बंगाल जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं को झालमुरी बनाकर खिलाया

बलरामपुर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत से देशभर में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। भाजपा संगठन से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग तरीकों से इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। रामानुजगंज दौरे पर पहुंचे सांसद चिंतामणि महाराज ने इस जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं को झालमुरी बनाकर खिलाया और सभी को बंगाल जीत पर धन्यवाद दिया। गुरुवार को सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज सुशासन तिहार में शामिल होने के लिए रामानुजगंज पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद बंगाल जीत का जश्न उन्होंने कार्यकर्ताओं को झालमुरी खिलाकर किया। सांसद ने अपने हाथों से झालमुरी बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को खिलाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल रहा। सरगुजा लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज ने रामानुजगंज दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में के अलावा दो और राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। मोदी जी, अमित शाह और नितिन गडकरी के नेतृत्व में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। ऐसा लग रहा था कि जीतना बहुत कठिन है लेकिन इनके मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे और आज बंगाल की जीत सबसे बड़ी जीत के तौर पर पूरा देश मान रहा है। आज हमारे कार्यकर्ता लोग जुटे हैं। इस जीत के लिए वहां की जनता जिन्होंने भाजपा पर भरोसा किया, उन्हें धन्यवाद देता हूं। यहां से भी जो हमारे कार्यकर्ता वहां काम करने गए थे वो सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं- चिंतामणि महाराज, सांसद सरगुजाछत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के जरिये गांव गांव में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सांसद विधायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं।

कोरबा में खाद्य सुरक्षा अभियान, नमूनों की जांच

कोरबा। कोरबा जिले में आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सही दवा, शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के अंतर्गत जिले भर में सघन जांच अभियान जारी है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न गुपचुप सेंटर, गन्ना जूस सेंटर, डेयरी दुकान और राशन दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान करतला क्षेत्र से चावल, नमक और शक्कर के नमूने संग्रहित किए गए। वहीं, जेलगांव स्थित केडिया ब्रदर्स से मिक्सचर का नमूना लिया गया। मेन रोड कोरबा स्थित श्री चन्द मार्केटिंग फर्म से धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर के नमूने संग्रहित किए गए। इसके अलावा 100 बेड हॉस्पिटल की कैंटीन से भी चावल और दाल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी फर्मों को खाद्य सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसमें लाइसेंस को प्रतिष्ठान में स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करना, परिसर में साफ-सफाई बनाए रखना, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय न करना शामिल है। साथ ही नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल कराने और कर्मचारियों का मेडिकल जांच कराने के निर्देश भी दिए गए। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विभाग का उद्देश्य मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकिंग, एक्सपायरी डेट और स्नस्स्ढ्ढ लाइसेंस नंबर जरूर जांचें। यह विशेष जांच अभियान 11 मई तक जिले भर में जारी रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सड़क अधोसंरचना को मजबूती, कांसाबेल-बगीचा मार्ग उन्नयन कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में सड़क अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कांसाबेल से बगीचा मार्ग के मजबूतीकरण एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लगभग 29 करोड़ 08 लाख 06 हजार रुपए की लागत से 39 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण मार्ग का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत सड़क मजबूतीकरण के साथ आवश्यक पुल-पुलियों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। कांसाबेल-बगीचा मार्ग क्षेत्र का अत्यंत व्यस्त संपर्क मार्ग है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, विद्यार्थी और व्यापारी आवागमन करते हैं। समय के साथ सड़क की स्थिति प्रभावित होने से लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी और परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ बनेगी। इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रा समय में कमी आएगी तथा व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार कर रही है।

संचालक योजना श्रीमती रोक्तिमा यादव को दी गई भावभीनी विदाई

रायपुर। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा

20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग की संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव को विभाग द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। अपने कार्यकाल के दौरान उनके उत्कृष्ट योगदान, कुशल नेतृत्व एवं समर्पित सेवाओं के लिए विभाग ने उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती रोक्तिमा यादव का स्थानांतरण आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर हुआ है। इस अवसर पर संयुक्त संचालक श्री सुरेश कुमार बंजारे, श्री सुरेश कुमार कश्यप, श्री डोमार सिंह वर्मा, उप संचालक श्रीमती माया तिवारी, श्री दिनेश कुमार तिवारी, श्रीमती सरोज सिंह कंवर तथा श्री जगत राम मधुकर सहित कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्रीमती यादव के कार्यकाल को प्रेरणादायक बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

दिव्यांग कार्तिकेय को मिला राशन कार्ड, अब खाद्य सुरक्षा योजनाओं का मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुशासन, संवेदनशीलता और त्वरित समाधान की भावना के साथ पहुंचाने आयोजित सुशासन तिहार प्रत्येक वर्ग के लोगों को राहत प्रदान कर रहा है। शासन द्वारा केवल समस्याएं सुनने तक सीमित न रहकर उनका त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसा ही एक भावुक करने वाला उदाहरण कोरबा शहर के सीतामढ़ी निवासी श्री कार्तिकेय जायसवाल के जीवन में देखने को मिला। वह दिव्यांग हैं और लंबे समय से राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रयासरत थे। कई बार प्रयास करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिससे उन्हें शासन की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कार्तिकेय सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में पहुंचे। शिविर में अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की गई और उनकी समस्या का निराकरण करते हुए राशन कार्ड स्वीकृत किया गया। आज आयोजित शिविर में श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने उन्हें राशन कार्ड प्रदान किया।

सुशासन तिहार : 15 मिनट में हाथों-हाथ मिला ड्राइविंग लाइसेंस

रायपुर। पेंड्रा विकासखंड के क्लस्टर ग्राम पंचायत देवरीकला में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में मटियाडांड निवासी हेमंत कुमार अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। शिविर में परिवहन विभाग के स्टॉल पर जब उन्हें पता चला कि यहाँ हल्के निजी वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने आवेदन किया। हेमंत कुमार बताते हैं, मुझे शुरुआत में यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लाइसेंस के लिए हफ्तों का समय लगता है, वह यहाँ महज 15 मिनट में बनकर तैयार हो गया। विभाग की तकनीकी सजगता और अधिकारियों के सहयोग से बिना किसी लंबी कतार या बिचौलियों के, हेमंत को उनका ड्राइविंग लाइसेंस सौंप दिया गया। उनके चेहरे की मुस्कान साय सरकार की कार्यक्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण बनी। सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन अब फाइलों में नहीं, बल्कि सीधे जनता के द्वार पर खड़ा नजर आ रहा है।

ताड़मेटला नक्सली हमला मामले में सभी आरोपी बरी

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का आया बयान, कहा- अभी न्यायालय का दरवाजा बाकी है

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ताड़मेटला नक्सली हमले के मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रकरण प्रस्तुत हुआ था लोअर कोर्ट में कन्विक्शन नहीं हो पाया था। विभिन्न कारणों से पुलिस, प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई थी उसमें भी कन्विक्शन नहीं हो पाया था। अभी न्यायालय का दरवाजा बाकी है।

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए, महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा, निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने का फैसला अवैध और अस्थिर है। निचली अदालत महत्वपूर्ण साक्ष्यों को समझने में विफल रही है, जिसमें आरोपी बरसे लखमा का मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिया गया इकबालिया बयान भी शामिल है, जिसमें उसने अन्य आरोपियों के साथ इस अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा, निचली अदालत बम निरोधक दस्ते द्वारा जब्त किए गए पाइप बमों और विस्फोटकों तथा अन्य सहायक सामग्री को भी समझने में विफल रही है। धारा 311 सीआरपीसी के तहत सात घायल सीआरपीएफ जवान, जो चश्मदीद गवाह थे, की जांच के लिए अभियोजन पक्ष के आवेदन को खारिज करना एक गंभीर त्रुटि है, जो मामले को कमजोर करती है।

अभियुक्तों को हत्या के कृत्यों के वास्तविक क्रियान्वयन से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी गवाही नहीं है। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने अभियुक्तों की पहचान अपराधियों के रूप में नहीं की है। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अभियुक्त का कथित इकबालिया बयान, जिसके अंतर्गत जब्त की गई विस्फोटक सामग्री, जिसमें पाइप बम, ग्रेनेड और राइफलें शामिल हैं, घटना स्थल से बरामद की गई थी, न कि आरोपी के कब्जे से। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामग्री को विस्फोटक प्रमाणित करने वाली एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे जब्ती का सबूत अप्रभावी हो जाता है। जांच त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि शस्त्र अधिनियम के तहत आवश्यक अभियोजन स्वीकृति का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है, निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्ति के फैसले के विरुद्ध राज्य

द्वारा दायर की गई अपील को खारिज किया जाता है। अभियुक्तों, प्रतिवादियों की दोषमुक्ति को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है। डिवीजन बेंच ने कहा, जांच में कई खामियां थीं, जैसे महत्वपूर्ण गवाहों की पहचान और जांच न होना, फोरेंसिक और तकनीकी प्रमाणों का अभाव, आरोपी को कथित अपराधों से जोड़ने वाले प्राथमिक साक्ष्यों का संग्रह न होना। मात्र संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, अपने आप में संदेह से परे प्रमाण की आवश्यकता का विकल्प नहीं हो सकता।

अर्बन नक्सलियों पर लगातार हो रही कार्रवाई पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद एटीएस में पहला एफआईआर हुआ। ऐसी कवायद चलती रहती है। नजर रखना आवश्यक होता है। दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं

वहीं सुशासन तिहार को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सुशासन तिहार को लेकर कांग्रेस की हवा निकल रही है। सुशासन तिहार इस वर्ष भी आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। अपने विषयों को रख रहे हैं और उसका निराकरण भी हो रहा है। विधायक, सांसद, मंत्री सभी प्रवास कर रहे। सारे विषयों पर चर्चा हो रही है और परिणाम भी जमीन पर दिख रहा है। जनता के काम होने पर भी किसी के पेट में पीड़ा है, तो उनका अपना प्रॉब्लम है। उसको कोई क्या करेगा।

सुशासन तिहार में मंत्री अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि विष्णु देव साय की सरकार है सुशासन है, तो सुदर्शन भी है। सीएम विष्णु देव साय ने कहा है कि वैधानिक काम समय पर पूरे नहीं करेंगे तो कठोर कार्रवाई होगी।

ताड़मेटला हो चाहे झीरम, असली दोषी सलाखों के बाहर : कांग्रेस

रायपुर। 76 जवानों की शहादत वाले ताड़मेटला नक्सली हमले ( ) में राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों के बरी के फैसले को बरकरार रखा है। इसे लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ताड़मेटला मामले में पुलिस ने जिन्हें दोषी बनाया, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। निचली अदालत पहली उन्हें बरी कर चुकी थी, अब हाईकोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में जब भी ऐसी गंभीर घटनाएं हुई असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, गरीब आदिवासियों को आरोपी बनाकर प्रस्तुत किया गया, उनके खिलाफ पुलिस कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। कांग्रेस पहले से कहते आ रहे है कि सरकार गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। ताड़मेटला का मामला हो चाहे झीरम का, असली दोषी सलाखों के बाहर हैं। सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई हुई है। घटना में सीआरपीएफ के 75 और जिला पुलिस बल का एक जवान शहीद हुआ, उनको हम न्याय नहीं दिला पाए। यह तत्कालीन भाजपा सरकार की अकर्मण्यता थी। प्रदेश में सरकार के सुशासन तिहार पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील शुक्ला ने हमला बोला और कहा कि सुशासन तिहार पूरी तरह विफल है, जनता को सरकार पर भरोसा नहीं है। जनता नहीं आ रही है। प्रशासन कुछ लोगों को एकत्रित कर फर्जी आवेदन प्रस्तुत करता है। फिजूल खर्ची कर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा आवेदन पिछली सुशासन तिहार के समय के पेंडिंग है, इसलिए लोग इस बार सुशासन तिहार में शामिल नहीं हो रहे हैं।

अस्पतालों की बदहाली पर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन

'सुविधाओं में जल्द सुधार नहीं किया तो आंदोलन की चेतावनी दी'

रायपुर। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज सीएमएचओ कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ी तो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा।

रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए।

प्रदर्शन के दौरान श्रीकुमार मेनन ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और आम जनता को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़

रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जो व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से संचालित हो रही थीं, वर्तमान सरकार में वे पूरी तरह चरमरा गई हैं।

उन्होंने कहा कि रायपुर के 70 में से 45 वार्डों में हमर क्लीनिक योजना शुरू की गई थी, जिससे छोटी-मोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़े अस्पतालों की ओर न जाना पड़े, लेकिन वर्तमान में इन क्लीनिकों की हालत खराब है और वहां स्टाफ की भारी कमी है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। हमर क्लीनिकों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण मरीजों को मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल रेफर किया जाता है, इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज के अभाव और अव्यवस्था के कारण कई मरीज इधर-उधर भटकते रहते हैं, और अंततः उनकी मौत तक हो जाती है।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता जनता की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेगी।

अब एक फोन कॉल पर मिलेगी बाजार और योजनाओं की जानकारी: वन मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वनांचल में रहने वाले वनोपज संग्राहकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और आईवीआरएस आधारित सूचना एवं संवाद तंत्र का शुभारंभ किया। यह नवाचार राज्य के 13 लाख से अधिक वनोपज संग्राहक परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह डिजिटल कदम छत्तीसगढ़ के वनांचल में आर्थिक क्रांति और जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगा।

संग्राहकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। संग्राहकों को टोल फ्री नंबर +91-9811125813 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल के बाद 911 से शुरू होने वाले नंबर से उपयोगकर्ता को कॉल बैक आएगा। कॉल रिसीव करते ही संग्राहक अपनी स्थानीय बोलियों जैसे हल्बी, गोंडी आदि में महत्वपूर्ण जानकारियां सुन सकेंगे। जानकारी सुनने के साथ ही उपयोगकर्ता अपनी राय, अनुभव और सुझाव भी रिकॉर्ड कर सकेंगे।

स्थानीय बोलियों को प्राथमिकता के कारण वनांचल की क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी मिलने से सूचनाओं का प्रसार अधिक प्रभावी होगा। जंगल, वनोपज संरक्षण, सतत संग्रहण, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी सीधे संग्राहकों तक पहुंचेगी। बाजार भाव और मूल्य संवर्धन की सही जानकारी मिलने से बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और संग्राहकों की आय बढ़ेगी। यह केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि संग्राहकों और शासन के बीच संवाद का एक मजबूत मंच बनेगा।

वनोपज संग्राहकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक जानकारी पहुँचाना या यह प्रयास राज्य के लाखों परिवारों के लिए आजीविका का संबल बनेगा। वनोपज संरक्षण वाणी तकनीक और जनसहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

सुशासन तिहार में समाधान की पहल शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2026 के तहत नगर पालिका परिषद कोण्डागांव द्वारा विकास नगर वार्ड क्रमांक-08 स्थित सामुदायिक भवन में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वार्ड क्रमांक 06 से 11 तक के नागरिकों की समस्याएं सुनने और उनका त्वरित निराकरण करने के लिए विभिन्न विभागों ने एक ही छत के नीचे सेवाएं उपलब्ध कराई। शिविर में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नगर पालिका परिषद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय डाक विभाग ने अलग-अलग स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन भी स्वीकार किए। शिविर के दौरान कुल 44 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 15 मांग संबंधी और 29 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल रहे। इनमें नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े सर्वाधिक 31 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 आवेदन दर्ज किए गए।

सरकार जनआस्था से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध: अग्रवाल

■ 34 लाख रूपए की लागत से तालाब सौंदर्यीकरण एवं छठ घाट निर्माण का किया भूमिपूजन, श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

रायपुर। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार जनआस्था से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक-सांस्कृतिक अधोसंरचना के विकास के लिए निरंतर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 में शनि मंदिर तालाब के सौंदर्यीकरण

एवं छठ घाट निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्र की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जनसुविधाओं को नई दिशा देने वाला साबित होगा। लगभग 34 लाख रुपये की लागत से किए जाने वाले इस कार्य के अंतर्गत शनि मंदिर तालाब का सौंदर्यीकरण, परिसर का व्यवस्थित विकास तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधायुक्त छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक आयोजनों एवं पर्वों के दौरान लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि क्षेत्र की स्वच्छता, सौंदर्य एवं सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक स्थल केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं होते, बल्कि समाज को जोड़ने, संस्कृति को जीवित रखने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम भी होते हैं। शनि मंदिर तालाब एवं छठ घाट के विकसित होने से क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण प्राप्त होगा।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि उनका संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और अंबिकापुर निरंतर प्रगति एवं विकास के नए आयाम स्थापित करे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी विकास कार्यों में सहभागिता निभाने और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में सहयोग करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। क्षेत्रवासियों ने इस विकास कार्य के लिए राज्य सरकार एवं मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।

मैदान में रोहित-कोहली तो स्टेडियम में सेलिब्रिटीज की रहेगी धूम

■ अंबानी परिवार भी होगा मौजूद, सुरक्षा में 8 आईपीएस समेत होंगे 1500 पुलिसकर्मी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर को 10 साल बाद आईपीएल मैचों की मेजबानी मिली है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैचों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेट फैंस के तैयार है। रविवार यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस देखने पहुंचेंगे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और रोहित शर्मा की पत्नी रितिका पहुंच सकती हैं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी को स्पोर्ट करने के लिए अंबानी परिवार के पहुंचने के आसार हैं। बॉलीवुड

हस्तियां भी मैच देखने आ सकती हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं।

राजधानी में एक ओर जहां क्रिकेट फैंस 10 और 13 मई को होने वाले मैच के लिए उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने हाईलेवल मीटिंग ली थी, जिसके बाद से सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई है। आईजी-डीआईजी और एसपी स्तर के 8 आईपीएस अफसरों के साथ 20 राजपत्रित अधिकारी और करीब 1500 जवान तैनात रहेंगे।

डीआईजी जितेन्द्र शुक्ला जायसवाल को सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया गया है, वह आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा के मार्गदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। 1200 पुलिस जवानों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अलग से 300 से ज्यादा जवान मौजूद रहेंगे।

5 रास्तों से पहुंच सकेंगे स्टेडियम

स्टेडियम पहुंचने के लिए 5 रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्टेडियम में 12 गेट से प्रवेश दिया जाएगा। पैवेलियन के लिए तीन गेट बनाए गए हैं।

रायपुर से आने वाले सेरीखेड़ी ओवरब्रिज, बलौदाबाजार और बिलासपुर वाले दर्शक धनेली बाईपास होकर नवागांव मंदिरहसौद की ओर, धमतरी-जगदलपुर से आने वालों को जंगल सफारी मार्ग और नवापारा राजिम से भी नवा रायपुर होते हुए स्टेडियम पहुंच सकते हैं।

रायपुर शहर से आने वाले वाहन तेलीबांधा, सेरीखेड़ी ओवरब्रिज और नवा रायपुर होते हुए स्टेडियम तिराहा पहुंचेंगे। इनके लिए पार्किंग व्यवस्था साई अस्पताल के पास और सेंध तालाब में की गई है। बिलासपुर, बलौदाबाजार और खरोरा की ओर से आने वाले वाहन रिंग रोड-3, विधानसभा चौक, मंदिरहसौद और नवागांव होते हुए स्टेडियम टर्निंग पहुंचेंगे। इन वाहनों की पार्किंग परसदा और कोसा पार्किंग में रहेगी दुर्ग-भिलाई से आने वाले वाहन टाटीबंध, पचपेढ़ी नाका, तेलीबांधा और सेरीखेड़ी मार्ग से होकर सत्य साई अस्पताल या सेंध तालाब पार्किंग तक पहुंचेंगे।

धमतरी और जगदलपुर की ओर से आने वाले वाहन अभनपुर, केंद्री और मंत्रालय चौक से कोटराभाठा होते हुए साई अस्पताल के पास निर्धारित पार्किंग स्थल का उपयोग करेंगे।महासमुंद और सरायपाली से आने वाले वाहन आरंग मार्ग से सीधे स्टेडियम टर्निंग पहुंचकर परसदा और कोसा पार्किंग में वाहन खड़े करेंगे। वहीं ए से जी श्रेणी तक के वाहन पास धारक सेरीखेड़ी, डॉ. खूबचंद बघेल चौक और कयाबांधा चौक होते हुए सीधे अपने आवंटित पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे।

हिंसा के बीच शांति की आस और नई सरकार का गठन

हरि वर्मा

बंगाल जल उठा है। चुनाव बाद चिंगारी फिर भड़क गई है। मां-मानुष वाली माटी लहूलुहान है। हिंसा, फायरिंग, आगजनी की घटनाओं ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। जनादेश के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा न देने का एलान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दे डाली है। संवैधानिक शीर्ष पद पर बैठीं मुख्यमंत्री ममता ने ही संवैधानिक संस्थानों और प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बंगाल में चुनाव बाद उपद्रव बहुत हैरान करने वाला नहीं, लेकिन निंदनीय जरूर है। हिंसक घटनाओं के बीच बंगाल में रामराज बहाल करना नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का यह कोई पहला वाकया नहीं है। अतीत दागदार रहा है। शुरू में तीन दशक तक वहां कांग्रेस का राज रहा। 1977 में जब पहली बार वाम मोर्चे ने कांग्रेस के हाथ से कुर्सी हथिया कर सत्ता के गलियारे में लाल झंडा गाड़ा, तब भी बंगाल की माटी खून से लाल हुई थी। चुनाव बाद की हिंसा में वाम-कांग्रेस समर्थक आपस में खूब भिड़े। खूनखराबे में कई जानें गईं। फिर 1977 से 2011 तक करीब 34 वर्षों तक राज करने वाले वाम मोर्चे को जब तृणमूल कांग्रेस ने गद्दी से उतारा तो त्रिकोणीय संघर्ष (कांग्रेस, वाम, तृणमूल समर्थकों के टकराव) का दौर शुरू हुआ। 2011 से 2016 के पांच वर्षों के तृणमूल राजकाज में 180 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुईं। 2021 आते-आते जब तृणमूल कांग्रेस के लिए भाजपा चुनौती साबित होने लगी, तब भी 29 हत्याएं और दुष्कर्म की 12 घटनाएं हुईं। इन हिंसक घटनाओं की ज्यादा वजह राजनीतिक रंजिश ही रही। 2021 आते-आते बंगाल में मानवाधिकार से जुड़ी 10,900 शिकायतें आईं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर यदि गौर फरमाएं तो ममता के 15 साल के राज में 75 लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए। भाजपा के कई कार्यकर्ता इन 15 वर्षों में मारे गए। ऐसा नहीं कि केवल राज्य सत्ता परिवर्तन के दौर में ही बंगाल की माटी ने हिंसा झेली। 2008 में पंचायत चुनाव के दौरान भी और नंदीग्राम-सिंगूर आंदोलन में भी 45 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी जंगलमहल इलाके में कांग्रेस, वाम, तृणमूल समर्थकों के त्रिकोणीय सियासी संघर्ष में 15 लोगों की जान गई। और अब 2026 में चुनाव नतीजे के तुरंत बाद भड़की हिंसा में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है। दफ्तर फूंके गए। फायरिंग हुई। लोकतंत्र फिर कराह रहा है। ऐसा नहीं कि हिंसा का यह अंदेशा पहले नहीं था। अमित शाह ने चुनाव के दौरान जब एक पखवाड़े तक बंगाल में प्रवास किया, तब वहां वर्षों से उपजे भय को भरोसे में बदलने के लिए कहा था। बंगाल में चुनाव के बाद भी 60 दिनों तक केंद्रीय बल रहेगा। इस भरोसे के बूते ही वहां आजाद भारत का अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान हुआ। चुनावी रैलियों में भी पीएम मोदी ने कहा था, गुंडे 4 मई के बाद देख लें। चुनाव आयोग ने विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि टकराव टल जाएं। जाहिर है, 4 मई को नतीजे आए, लेकिन अंदेशे के अनुरूप ही 24 घंटे के भीतर ही सियासी रंजिश की चिंगारी सुलग पड़ी। ताजा हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। उपद्रवी कोई हो, उसे कतई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जाहिर है यह सत्ता परिवर्तन का दौर है। 9 मई को नई सरकार शपथ लेगी। आने वाली सरकार के लिए रामराज बहाल करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में प्रदेश की नई सरकार हो या केंद्र यानी डबल इंजन की सरकार के लिए रामराज स्थापित करने के लिए कड़े और बड़े एक्शन की उम्मीद की जानी चाहिए।

सोमनाथ हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है

नरेंद्र मोदी

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है = 'प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्'। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझायी नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आये और गये, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे।

लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज

ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभायी। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की।

महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर ने, जिनकी 300वीं जयंती मनायी जा रही है, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही, हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

पूरे भारत में 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। तेरह नवंबर, 1947 को दिवाली के समय उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, 'इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नये उत्साह से भर दिया। दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। वर्ष 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर उसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्तूबर, 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2001 को गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। उसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनायी जा रही थी। उस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने उसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया। डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई, 1951 को अपने भाषण में कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं। पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान भी बनाये रखी है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है। सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आये लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है।

इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जायेगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है।

मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब इसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखा। आप समझ पायेंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

तथ्य शब्द का अर्थ सत्य है और उ शब्द वितर्क द्योतक है: अर्थात् जिसकी सत्यता में वितर्क हो वह उतथ्य कहा जाता है। अत: यह जीव- जीवरूपेण सत्य किंवा ब्रह्मविद् ब्रह्मव भवति के अनुसार ब्रह्मरूपेण सत्य है? ऐसा विचार जीवात्मा के विषय में निरन्तर बना रहता है।

द्वैत-अद्वैत-विशिष्टाद्वैत आदि सिद्धान्त इसी एक उ के चमत्कार हैं। ममता शब्द की विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रचलित भाषा में भी किसी वस्तु में विशेष आसक्त होना या उसमें रागाधिक्य रखना, ममत्व-ममता किंवा मामता कही जाती है, जो कि माया का ही विशद स्वरूप है। दीर्घतमा का अर्थ घोर अन्धकार है, जिसे दूसरे शब्दों में अज्ञान या मोह कहा जा सकता है। इसी प्रकार वीर्य शब्द भी पराक्रम का पर्याय्य है। अत: आध्यात्मिक पक्ष में इसका सीधा अर्थ यही होगा कि जीमात्मा रूप उतथ्य की स्त्री ममता ममत्वयुक्त तादृश वृत्ति के गर्भ में मोहरूप दीर्घतमा थे।

बृहस्पति मन ने इस वृत्ति में अपने वीर्य-सामर्थ्य का संचार करना चाहा, परन्तु जब तक ममता के गर्भ में मोह घुसा बैठा हो तब तक मानसी शक्ति का संचार होना सर्वथा कठिन है। वेद में इसी भाव को इस प्रकार प्रकट किया है-

अन्धं तम: प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।

(यजु: 40 । 12)

अर्थात्- जो मनुष्य अविद्या के चंगुल में फंस जाते हैं वह घोर अन्धकार को प्राप्त होते हैं। अत: मन के हजार बार प्रयत्न करने पर भी ममता-गर्भस्थ मोह मानसिक बल का प्रवेश नहीं होने देता। कदाचित् गह मन:रूप बृहस्पति यथातथा अपने वीर्य सामर्थ्य को ममतावृत्ति के सन्निधान में भी प्रस्खलित करदे- फैलादे, तो उससे झारमज्ञान रूप भरद्वाज उत्पन्न होता है।

क्रमश: ...

गोपाल कृष्ण गोखले

गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 9 मई 1866 को हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे। महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखा और इसीलिए वह राष्ट्रपिता के राजनीतिक गुरु कहलाए।

गोखले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके पिता कृष्ण राव पेशे से क्लर्क थे। अपनी शिक्षा दीक्षा के दौरान वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। पढ़ाई में सराहनीय प्रदर्शन के लिए जब उन्हें सरकार की ओर से 20 रुपए की छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हुई तो उन्हें शिक्षकों और सहपाठियों की काफी सराहना मिली।

इतिहासकार एच.एन. कुमार का कहना है कि अधिकतर लोग गोखले को सिर्फ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में ही जानते हैं लेकिन वह सिर्फ राष्ट्रपिता ही नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। उनका मानना है कि यदि आजादी के समय गोखले जीवित होते तो शायद जिन्ना देश के बंटवारे की बात रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गोपाल कृष्ण गोखले ने देश को सबसे बड़ा योगदान दिया था। बता दें कि देश को समझने की सीख राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोखले ने ही दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को पूरा देश घूमकर भारत को समझने की सलाह दी थी। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी गोखले के जबरदस्त प्रशंसक थे। गोखले उन नेताओं में थे जिनसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे।

इतिहास के प्रोफेसर के.के. सिंह का कहना है कि गांधी जी को अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा गोखले से ही मिली थी। उन्हीं की प्रेरणा से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के आमंत्रण पर 1912 में गोखले खुद भी दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद की निन्दा की तथा इसके खिलाफ आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

जन नेता कहे जाने वाले गोखले एक नरमपंथी सुधारवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही देश में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ भी संघर्ष किया। वह जीवनभर हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। यह बात अलग है कि बाद में जिन्ना देश के बंटवारे का कारण बने और गोखले द्वारा दी गई शिक्षा का पालन नहीं किया।

गोखले पुणे के फर्ग्युसन कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने इस कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी जारी रखीं। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सर्वेंट्स सोसायटी ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य भी थे।

भारत भूमि को गुलामी से आजाद कराने के लिए जन्मे इस वीर सपूत का 19 फरवरी 1915 को निधन हो गया। ऐसे महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले की देशभक्ति आध्यात्मिकता पूर्ण थी।

जब सोनिया गांधी ने राहुल के प्रस्ताव को रोका

हरीश गुप्ता

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुप्त गलियारों में, तमिलनाडु की पहेली रणनीति से ज्यादा पारिवारिक विवाद का रूप लेने लगी थी। राहुल गांधी बेचैन और अधीर होकर, चुपचाप एक राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी कर रहे थे - पुराने दिग्गज दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को छोड़कर अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) के साथ साहसिक गठबंधन की संभावना तलाश रहे थे। संकेत सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट थे। इस साल जनवरी की शुरुआत में सेंसरशिप विवादों पर विजय के प्रति राहुल का सार्वजनिक बचाव कोई आकस्मिक संयोग नहीं था - यह एक राजनीतिक संकेत था।

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों में पर्दे के पीछे की बातचीत, दूतों द्वारा स्थिति का जायजा लेने और एक नई दक्षिणी रणनीति तैयार किए जाने की चर्चा थी। द्रमुक के अधीन रहने से ऊब चुकी राज्य इकाई भी पूरी तरह से इसके विरोध में नहीं थी। लेकिन द्रमुक कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। वरिष्ठ नेता कनिमोझी चुपचाप दिल्ली के लिए रवाना हुईं और जनवरी की ठंडी शाम को 10 जनपथ पर उतरीं। उनका संदेश स्पष्ट था : कोई भी विवाद न छेड़ें। फिर भी, राहुल अपने रुख पर अड़े रहे।

गतिरोध गहराता गया और तमिलनाडु में गठबंधन का समीकरण टूटने के कगार पर पहुंच गया। ऐसे में सोनिया गांधी का आगमन हुआ। तीन मार्च को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने अपने विशिष्ट दृढ़ निश्चय के साथ हस्तक्षेप किया। फोन किए गए, सीमाएं तय की गईं और एमके स्टालिन से सीधा संपर्क स्थापित किया गया। संदेश स्पष्ट था- कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा। डीएमके गठबंधन कायम रहेगा। राहुल का प्रयोग शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। अनिच्छा से ही सही, पार्टी ने बात मान ली।

सीटों का बंटवारा तय किया गया और एकता का दिखावा फिर से कायम किया गया। यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने किसी भी संयुक्त रैली को

संबोधित नहीं किया और दूरी बनाए रखी। लेकिन राजनीति में समय का खेल बहुत क्रूर होता है। जैसे-जैसे नतीजे आने शुरू हुए, कानाफूसी तेज होती गई- क्या राहुल ने वह देख लिया था जो दूसरे नहीं देख पाए?

टीवीके के उदय ने जमीनी हकीकत में बदलाव का संकेत दिया, जिस पर कांग्रेस ने आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। फिलहाल, अनुशासन ने सहज प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली। राहुल ने टालमटोल किया, सोनिया गांधी ने फैसला लिया। और तमिलनाडु में कहीं न कहीं, एक छूटा हुआ अवसर खामोशी से नजर आता रहा।

कई वर्षों तक, आम आदमी पार्टी के दस सांसदों के सुगठित लेकिन जुझारू राज्यसभा गुट ने अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रभाव डाला और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हर मोड़ पर चुनौती दी। यहां तक कि जब स्वाति मालीवाल ने गठबंधन तोड़ा, तब भी यह किला डटा रहा- दरारें दिखाई दीं, लेकिन कोई पतन नहीं हुआ। फिर वो पल आया जिसने सारी कहानी बदल दी। अरविंद केजरीवाल के कभी चहेते रणनीतिकार रहे राघव चड्ढा जब पार्टी में अपनी पकड़ खोने लगे, तो हलचल शुरू हो गई। फुसफुसाहटें दबी हुई चर्चाओं में बदल गईं; बेचैनी को एक दिशा मिल गई। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बनने से पहले ही हलचल का आभास हो गया था। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसमें राजधानी की किसी क्लासिक साजिश के सभी तत्व मौजूद थे।

दिल्ली की उमस भरी रात में, नियमित राजनीतिक गतिविधियों के समय के काफी बाद, आम आदमी पार्टी के सात सांसद अमित शाह के आवास पर गुप्त रूप से पहुंचे और एक बंद कमरे में बैठक की, जिसे अंदरूनी सूत्रों ने निर्णायक बताया है। यह महज शिष्टाचार भेंट नहीं थी। शाह ने अपने विशिष्ट सधे हुए अंदाज में एक ठोस राजनीतिक मुद्दा रखा- पंजाब की ठप पड़ी सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का अनियमित क्रियान्वयन और आम आदमी पार्टी के भीतर प्रासंगिकता के लिए सिकुड़ता दायरा। जब बैठक आधी रात के करीब समाप्त हुई, तब तक पासा पलट चुका था।

दिल्ली में हमेशा की तरह, संख्याएं शोर से कहीं अधिक निर्णायक साबित हुईं। दो-तिहाई से अधिक दल-बदल के लिए तैयार थे, और दल-बदल विरोधी कानून बाधा से एक पुल में तब्दील हो गया। केजरीवाल का किला धमाके के साथ नहीं गिरा - उसे चुपचाप अंदर से तोड़ दिया गया। राजधानी के इस गुप्त सत्ता संघर्ष में, यह एक विद्रोह से कहीं अधिक आधी रात को की गई एक कार्रवाई थी - तेज, शांत और बेहद प्रभावी।

एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण रणनीतिक चर्चाओं में हलचल मची हुई है, वहीं भारत के सैन्य तंत्र में एक शांत लेकिन उतनी ही गहन उथल-पुथल चल रही है: अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा? जनरल अनिल चौहान का विस्तारित कार्यकाल 30 मई, 2026 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में यह दौड़ निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है- हालांकि आधिकारिक तौर पर, यह पद सभी की दावेदारी के लिए खुला है। समय को देखते हुए मामला और भी पेचीदा हो गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के। त्रिपाठी, दोनों कुछ ही महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे उनके नाम इस पद के लिए दावेदारी में आ गए हैं। स्वाभाविक रूप से, पैरवी तेज हो गई है, और इस बात पर पैनी नजर रखी जा रही है कि सत्ता का संतुलन कैसे बदलेगा। हालांकि, दिल्ली के सुरक्षा हलकों में चल रही चर्चा से संकेत मिलता है कि परिणाम केवल सेनाओं के भीतर ही सीमित नहीं रह सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को इस तरह की नियुक्तियों में एक प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। उनके सैन्य सलाहकार, लेफ्टिनेंट जनरल एस। राजा सुब्रमणि, एक गंभीर दावेदार के रूप में उभरे हैं - जो चौहान के इसी पद से सीडीएस तक के सफर को दर्शाते हैं। चौहान और भारत के पहले सीडीएस, दिवंगत जनरल बिपिन रावत, दोनों को डोभाल के रणनीतिक दृष्टिकोण के करीब माना जाता था। हालांकि, किसी सेवानिवृत्त सेना जनरल की एक और नियुक्ति से नौसेना और वायु सेना में असंतोष पैदा हो सकता है, जो लंबे समय से सेना के संस्थागत प्रभुत्व का विरोध करती रही हैं। आखिरकार, सीडीएस पद का उद्देश्य ही सभी सेवाओं में समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना था। अब जब पात्रता मानदंडों का दायरा बढ़ाकर सेवारत और सेवानिवृत्त तीन-सितारा अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया है, तो सरकार के पास लचीलापन है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या वह इस लचीलेपन का उपयोग संतुलन को मजबूत करने के लिए करती है- या निरंतरता को बनाए रखने के लिए।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के साथ ही सारा ध्यान जीत से हटकर इस अहम सवाल पर केंद्रित हो गया है कि ममता बनर्जी की जगह कौन लेगा? भाजपा मुख्यालय में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बंगाल को भगवा खेमे से पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है? आखिरकार, भाजपा 18 राज्यों में अकेले सत्ता में है। नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, खासकर महिला आरक्षण को बढ़ावा देने के बाद, नारी शक्ति को पार्टी की राजनीति का केंद्रबिंदु बताते हुए। यह प्रस्ताव देखने में आकर्षक लगता है। एक महिला मुख्यमंत्री विपक्ष के हमलों को कमजोर कर देगी और भाजपा के महिला समर्थक रुख को मजबूती प्रदान करेगी।

आज का इतिहास

1915 ब्रिटिश सेनाओं ने पश्चिमी मोर्चे पर अनौपचारिक रूप से बैटल ऑफ ऑबर्स रिज की शुरुआत की, जो कि फ्रेंचोस्कैंड की बड़ी लड़ाई का हिस्सा था।
1916 अमेरिकी कार्गो शिप एसएस रोयोनो में कैलिफोर्निया के तट पर 47 लोग मारे गए।
1918 प्रथम विश्व युद्ध-जर्मनी ने ओस्टेंड के बेल्जियम बंदरगाह को फिर से बनाने के लिए ब्रिटेन के दूसरे प्रयास को रद्द कर दिया।
1927 कैनबरा ने 9 मई, 1927 को प्रोविजनल पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन के साथ मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में बदल दिया। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय शहर है, जो ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र के उत्तरी छोर पर स्थित है।
1945 चैनल द्वीपों का जर्मन का कब्जा समाप्त हुआ।
1947 विश्व बैंक ने अपना पहला कर्जा फ्रांस को दिया था।
1949 रेनियर III 56 साल के शासनकाल की शुरुआत करते हुए, मोनाको के राजकुमार बन गए, जो उन्हें 20 वें राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में से एक बना देगा।
1951 स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित ओपेरा हाउस एक आग हादसे में नष्ट हो गया।
1956 फिलीपींस और जापान के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करते हुए फिलीपींस और जापान के बीच 9 मई 1956 को मलाकानेंग पैलेस में फिलीपींस और जापान के बीच युद्ध सुधार और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
1960 यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह घोषणा की कि जन्म नियंत्रण के लिए सेरेल के एनोविड के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे यह पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली बन जाएगी।
1960 बर्थ कंट्रोल पिल वैध करने वाला अमेरिका पहला देश बना।
1962 पहला सफल चंद्र लेजर का प्रयोग 9 मई, 1962 को लेक्सिंगटन में किया गया था, जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम ने लेजर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह से परावर्तित लेजर दालों का अवलोकन किया।
1975 पहली विद्युत टंकण मशीन बनायी गयी।
1977 एम्स्टर्डम में होटल पोलेन को आग से नष्ट कर दिया गया, जिसमें 33 मौतें और 21 घायल हुए।
1979 प्रख्यात ईरानी यहूदी हबीब एलघेनियन को ईरान के यहूदियों के सामूहिक पलायन को ट्रिगर करने वाले विभिन्न आरोपों के एक क्रांतिकारी न्यायाधिकरण द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद निष्पादित किया गया था।
1979 साल्वाडोरैन सिविल युद्ध शुरू हुआ।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन है वैचारिक बदलाव का संकेत

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों को केवल एक राजनीतिक दल की जीत या हार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह परिणाम उस वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति के भीतर सुलग रहा था। वर्षों तक बंगाल को एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां कथित रूप से जाति, धर्म और पहचान की राजनीति नहीं चलती, बल्कि विचारधारा, वर्ग-संघर्ष और बंगालियत की राजनीति प्रभावी रहती है। किंतु 2026 के चुनाव परिणामों ने इस स्थापित धारणा को गहराई से चुनौती दी है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान में आए परिवर्तन का भी संकेत है। मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या वैचारिक रोमांटिसिज्म के आधार पर मतदान नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य को भी ध्यान में रख रहा है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता को अनेक विश्लेषक एक प्रकार के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देख रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बंगाली अस्मिता और हिंदू पहचान के बीच एक वैचारिक द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं को बंगाल की संस्कृति और क्षेत्रीय गौरव का संरक्षक बताया, जबकि भाजपा ने राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और सांस्कृतिक चेतना को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। वास्तव में बंगाल की ऐतिहासिक चेतना कभी संकुचित नहीं रही। यह वही भूमि है जहाँ से स्वामी विवेकानंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। वंदे मातरम् का उद्घोष भी इसी भूमि से निकला। इसलिए जब बंगाल में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की चर्चा होती है, तो वह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ भी ग्रहण कर लेता है। भाजपा ने इसी ऐतिहासिक चेतना को पुन: जागृत करने का प्रयास किया। दुर्गापूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू धार्मिक प्रतीकों को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक बहसें पिछले वर्षों में सामने आईं, उन्होंने हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को यह महसूस कराया कि उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां राजनीतिक विवाद का विषय बन रही हैं। परिणामस्वरूप एक बड़ा वर्ग अपनी पहचान के प्रश्न पर अधिक मुखर हुआ।

पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से अल्पसंख्यक वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि ममता बनर्जी सरकार ने संतुलित शासन के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। चाहे इमाम भत्ता का मुद्दा हो, धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासनिक निर्णय हों या सीमावर्ती जिलों में बदलता जनसांख्यिकीय

संतुलन-इन सभी विषयों ने धीरे-धीरे हिंदू समाज के भीतर असंतोष को जन्म दिया। यह असंतोष केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी था। अनेक लोगों को यह लगने लगा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता का अभाव है। भाजपा ने इसी भावना को राजनीतिक रूप दिया। उसने यह संदेश देने का प्रयास किया कि उसकी राजनीति केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सुरक्षा स्थापित करने की राजनीति है। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान जय श्रीराम जैसे नारे केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहे, बल्कि वे एक प्रकार के राजनीतिक प्रतिरोध और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक बन गए।

इस चुनाव में हिंदी भाषी मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में हिंदी भाषी समाज का प्रभाव बढ़ा है। यह वर्ग लंबे समय से स्वयं को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करता रहा था। भाजपा ने इस वर्ग को संगठित करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इस चुनाव को केवल हिंदी बनाम बंगाली के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। वस्तुत: भाजपा ने हिंदी भाषी और स्थानीय हिंदू समाज के बीच एक वैचारिक सेतु बनाने का प्रयास किया। उसने यह संदेश दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर है। यही कारण है कि बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भाजपा को व्यापक समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल कभी वामपंथ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। वर्ग-संघर्ष, श्रमिक राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा यहाँ की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रही। लेकिन समय के साथ यह विचारधारा जमीन से कटती चली गई। वामपंथी दल जनता की नई आकांक्षाओं, युवाओं की उम्मीदों और बदलते सामाजिक यथार्थ को समझने में असफल रहे। आज का युवा केवल वैचारिक भाषण नहीं चाहता- वह रोजगार, सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्मान और विकास चाहता है। यही कारण है कि वामपंथ धीरे-धीरे राजनीतिक हाशिये पर पहुँच गया। भाजपा ने इस खाली स्थान को भरते हुए स्वयं को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता को अनेक लोग डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों से भी जोड़कर देख रहे हैं। डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया और राष्ट्रीय एकात्मता को सर्वोपरि माना। बंगाल की राजनीति में भाजपा का उभार कहीं न कहीं उसी विचारधारा की पुनर्स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि बंगाल अब केवल क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह पुन: राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इन चुनाव परिणामों को हिंदू पुनर्जागरण कहा जा सकता है? इसका उत्तर पूरी तरह सरल नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि हिंदू समाज के भीतर अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक नई जागरूकता अवश्य उत्पन्न हुई है। यह जागरूकता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक अभिव्यक्ति का भी रूप ले रही है। हालांकि किसी भी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक चेतना सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के साथ संतुलित रहे। यदि पहचान की राजनीति संवाद और समावेशिता के बजाय टकराव का रूप लेती है, तो वह लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए बंगाल के इस परिवर्तन को केवल विजय उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी और आत्ममंथन के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। भाजपा की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल अब राजनीतिक रूप से अपवाद नहीं रहा। यहाँ भी वही प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं जो देश के अन्य हिस्सों में प्रभावी हैं-सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सामाजिक संतुलन। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। यदि भाजपा वास्तव में बंगाल में एक नए युग की शुरुआत करना चाहती है, तो उसे केवल वैचारिक नारों तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे रोजगार, उद्योग, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर ठोस कार्य करना होगा। बंगाल की धरती ने हमेशा भारत को विचार, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रवाद की नई दिशा दी है। आज फिर इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा है। आने वाला समय तय करेगा कि यह परिवर्तन केवल राजनीतिक लहर साबित होगा या वास्तव में बंगाल के सांस्कृतिक और वैचारिक पुनर्जागरण का आधार बनेगा।

वामपंथ ने अपनी आखिरी सरकार भी गंवाई

कृष्ण प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल के शोर में केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों की ओर देश का कुछ कम ही ध्यान जा रहा है - हालांकि राजनीतिक लिहाज से वे भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हाथों वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की करारी हार के बाद वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे के साथ ही देश में वामपंथी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है।

यह पांच साल पहले ही खत्म हो जाता, अगर पिछले विधानसभा चुनाव में विजयन के कामकाज से खुश केरल के मतदाता उन्हें 'बख्श' नहीं देते। लेकिन इस बार उनकी छवि भी उनकी सत्ता नहीं बचा पाई और वे 'अब तक के आखिरी वामपंथी मुख्यमंत्री' के रूप में भूतपूर्व हो गए।

यहां याद किया जाना चाहिए कि ई।एम।एस। नंबूदरीपाद के मुख्यमंत्रित्व में देश की पहली वामपंथी सरकार भी 5 अप्रैल, 1957 को इसी राज्य में बनी थी, उसके राज्य बनने के बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में। और इस मायने में अभूतपूर्व थी कि उसके रूप में न केवल भारत, बल्कि दुनिया में कहीं भी पहली बार किसी कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में सत्ता हासिल हुई थी।

सच कहें तो वामदलों के नेता संसदीय कहें अथवा चुनावी राजनीति में उतरे तो उसे अपनी क्रांतिकामना के लिए इस्तेमाल करने के मंसूबे से थे, मगर समय के साथ खुद उसके हाथों इस्तेमाल होकर रह गए हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद जतन से विकसित की गई 'सारी मध्यवर्गी पार्टियों के सबसे प्रतिबद्ध वैचारिक प्रतिपक्ष' की अपनी छवि भी वे नहीं बचा पाए हैं।

आज वामदलों में एका के बजाय बिखराव बढ़ता जा रहा है और कई कम्युनिस्ट पार्टियां अपने महासचिवों की जेबों में रहकर उनकी बौद्धिक भूख के शमन का जरिया भर रह गई हैं। दूसरी ओर कई वामपंथी पार्टियों के नेता उतने भी प्रतिबद्ध या 'मेंटली इक्विप्ड' नहीं रह गए हैं, जितने कभी उनके साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे।

उन्होंने एक दूजे के लिए बुर्जुआ, संशोधनवादी, सुधारवादी और संसदवादी आदि एक से बढ़कर एक गालियां विकसित कर डाली हैं और उन्हें लेकर अपने ही शिविर में 'हत्याएं' करते रहते हैं। माकपा से जुड़े अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने तो एक समय अपनी ही पार्टी की केरल इकाई पर 'सामंती स्टालिनवाद' और उदारवाद की वर्चस्वता की शिकार होने की तोहमत लगाई थी।

सच्ची बात तो यह है कि आज वामदलों को पुनर्जीवन के लिए नए फार्मूलेशनों और रणनीतियों की बेहद सख्त जरूरत है क्योंकि पुरानी कम्युनिस्ट थीसिसों का नए बदलावों के परिप्रेक्ष्य में युगानुरूप परीक्षण किए बिना उनकी बात नहीं बनने वाली है। इस परीक्षण के अभाव का ही नतीजा है कि लगभग एक साथ सक्रिय होने वाली दो जमातों में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि वह राजनीति से परे रहकर संस्कृति के ही क्षेत्र में काम करेगा, उसने काम करते-करते अपने राजनीतिक फ्रंट की मार्फत लगभग सम्पूर्ण देश की राजनीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और संस्कृति के क्षेत्र में काम से परहेज कर चौबीसों घंटे जनपक्षधर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां राजनीति के हाशिये में चली जा रही हैं।

जो दलित व पिछड़े कभी वामपंथ के आधार थे, निराश होकर उनके भी कुछ हिस्से यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि वामपंथी दल क्रांति करने नहीं, क्रांति रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वर्ग के चक्कर में उन्होंने वर्ण की हकीकतों को किंचित भी नहीं समझा है।

पश्चिम बंगाल में टूटती संवैधानिक मर्यादाएं

सुरेश हिंदुस्तानी

पश्चिम बंगाल के साथ पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात् जो तस्वीर निर्मित हुई है, वह कड़वाहट और मिठास दोनों का ही स्वाद दे रही है। विपक्ष के राजनीतिक दल जहाँ एक ओर तमिलनाडु और केरल के मनमाफिक परिणाम देखकर मिठास का स्वाद ले रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को सभी विपक्षी दल भाजपा की प्रायोजित जीत के रूप में प्रचारित करने का असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को इस बार जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लेकिन ममता बनर्जी कुर्सी से चिपके रहने के अंदाज में पराजय को स्वीकार करने का मानस नहीं बना पा रही हैं। लोकतान्त्रिक मर्यादा के तहत उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा न करके एक प्रकार से लोक के निर्णय को ठेंगा दिखाने का कार्य कर रही हैं। खास बात यह है कि विपक्ष के कुछ अन्य दल भी तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के इस कदम का समर्थन करती हुई लग रही हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन यह विरोध संवैधानिक मर्यादायों के तहत ही होना चाहिए।

देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, ज़ब चुनाव में पराजित हो जाने के बाद मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देने से मना कर रहा है, ममता बनर्जी का यह रवैया निश्चित ही जनमत के साथ विश्वासघात ही कहा जाएगा। लोकतंत्र का असली आशय यही होता है कि जनता अपने बीच में से अपने प्रतिनिधि चुनकर अपनी सरकार बनाती है। जनता ने जनादेश दे दिया है। विपक्ष को भी यह स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम यह संदेश प्रवाहित कर रहे हैं कि अब देश में तुष्टिकरण के दिन ख़त्म हो गए हैं। जनता भी ऐसा ही चाहती है। मजेदार तथ्य यह है कि बंगाल के चुनाव के साथ ही पांच राज्य असम, केरल, तमिलनाडु और पंडिचेरी में भी चुनाव हुए असम को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में परिणाम सत्ता के विरोध में ही आए, लेकिन सवाल यह है कि इन राज्यों के परिणाम पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। इसके पीछे यही कारण माना

जा रहा कि वहां भाजपा नहीं जीती। भाजपा की जीतना विपक्ष को कभी नहीं पचा। विपक्ष का व्यवहार ऐसा होता जा रहा है जैसे ये केवल सत्ता के लिए ही बने हैं। चुनाव में जय पराजय होती ही है, केवल एक को ही विजय मिलती है।

पश्चिम बंगाल के बारे में यह सभी जानते हैं कि ममता सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। जनता भी इस भ्रष्टाचार से त्रस्त रही और प्रशासनिक अधिकारी भी। इसी के चलते तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के विरोध में एक राजनीतिक हवा बनी। भाजपा ने अपने प्रचार के दौरान ममता के भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। इसके विपरीत विपक्ष के अन्य दल भी इन मुद्दों पर मुखर रहे। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से ममता को निशाने पर लिया। इसका आशय स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के विरोध में लहर थी। दूसरी एक और प्रमुख बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में पिछले जितने भी चुनाव हुए, उनमें हिंसा के माध्यम से मतदाताओं को भयभीत करने का काम भी खुलेआम हुआ। ऐसा कोई भी चुनाव नहीं हुआ, जिसे हिंसा मुक्त कहा जा सकता हो। इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने हिंसा मुक्त चुनाव करके दिखा दिया। इसी कारण आम मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्र तक पहुँचने में सफल हुआ। इसी ने भाजपा की राह आसान की।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि वहां की मतदाता सूची से फर्जी नाम विलोपित किए गए। इन नामों में कई तो ऐसे थे, जो इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए इसे खास मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रति वर्ष मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने का क्रम चलता है। बंगाल का मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुडा था, इसलिए वहां एसआईआर जरुरी था। इससे जहाँ विदेशी मतदाता चुनाव में वोट का प्रयोग करने से वंचित हो गया, वहीं ऐसे मतदाता भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके, जो फर्जी थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व के चुनाव में यह वोट भी उपयोग में आते थे, इनके वोट कैसे पड़ते थे और कौन उंगली से बटन दबाता था, इसमें भले ही संदेह हो, लेकिन इसका आरोप तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर ही लगते थे। इसी हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों की तैनाती कराई। सुरक्षा बल केवल नागरिक सुरक्षा एवं भय मुक्त मतदान के लिए ही लगाया, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष के कई राजनीतिक दलों ने उनकी निष्ठा पर ही सवाल उठा दिए।

पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में ऐसे कई कारण रहे जो भाजपा की जीत और तृणमूल कांग्रेस की हार में काफी प्रभावी रहे। उसमें तृणमूल सरकार विरोधी लहर तो थी ही, साथ ही जो मुस्लिम वोट पूरा का पूरा तृणमूल को मिलता था, इस बार नहीं मिल सका। उसके पीछे मुसलमान नेताओं की सक्रियता रही। इस चुनाव में एक ओर ओवैसी की पार्टी मैदान में थी, वहीं हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी बनाकर ममता की परेशानी में बढ़ोत्तरी की। इस कारण मुसलमान वर्ग के वोट निश्चित ही विभाजित हो गए। इसके साथ ही राज्य का हिन्दू मतदाता कुछ ज्यादा सक्रियता के साथ मैदान में उतर आया। यह मतदाता निश्चित ही भाजपा के पक्ष में गया। इसलिए विपक्ष की ओर से यह कहना कि एसआईआर के कारण या चुनाव आयोग द्वारा भाजपा का साथ देने के आरोप प्रथम दृष्टि में ही तर्कहीन से लगते हैं। अब ममता बनर्जी को अपनी हार की समीक्षा करनी ही चाहिए, जो कमियां रही, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

चुनाव परिणाम के बाद आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। इसमें विपक्ष बिना प्रमाण के भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा

क्षेत्रीय पार्टियों के लिए गंभीर संक्रमण काल

राजेश बादल

भारतीय लोकतंत्र इन दिनों संक्रमण काल से गुजर रहा है। इस कालखंड में अनेक विकराल चुनौतियां हैं और पूंजीगत महामारियां भी। निश्चित रूप से आजादी के बाद हिंदुस्तान ने जिस सामुदायिक नेतृत्व वाली जम्हूरियत को स्वीकार किया था उसमें प्रत्येक व्यक्ति और पार्टी को उभरने का अवसर दिया गया था। यह एक ऐसी पवित्र भावना थी जो दुनिया के नक्शे पर उभरे एक स्वतंत्र देश के पुनर्निर्माण अनुष्ठान में हर नागरिक को आहुति देने का मौका देना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।

जैसे-जैसे संसार में लोकतंत्र के नए अत्याधुनिक संस्करण आते गए, उनमें धनबल, बाहुबल, सैनिक ताकत और तीव्र महत्वाकांक्षा की बुराइयां दाखिल होती गईं। भारत पर भी उसका असर पड़ा। धीरे-धीरे यह जहर देश की देह में इतना फैला कि सभ्य लोकतंत्र की मूल मंशा खो गई। आज इस शासन प्रणाली का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, वह स्वस्थ नहीं है। यह अब केवल मतदान के जरिये सत्ता में आने की चाबी बनकर रह गया है।

हाल ही में संपन्न कुछ विधानसभाओं के चुनाव परिणामों का हम गहराई से विश्लेषण करें तो पाते हैं कि सबसे ज्यादा झटका क्षेत्रीय पार्टियों को लगा है। बंगाल हो अथवा तमिलनाडु, केरल हो या असम- इन सभी में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में प्रादेशिक पार्टियों ने दम तोड़ दिया। अपवाद के तौर पर हम तमिलनाडु को मान सकते हैं। वहां टीवीके (तमिलगा वेत्री कषगम) की जीत को आप आम आदमी पार्टी की तरह एक नए क्षेत्रीय दल का धूमकेतु की तरह उदय मान सकते हैं।

लेकिन तमिलनाडु में अभिनय के सहारे जनमानस में छवि अंकित करना और फिर सियासत करना परंपरा बन चुका है। चुनाव के समय मुफ्त उपहारों की झड़ी लगा देना दक्षिण भारत के इस हिस्से में अब तंत्र का हिस्सा बन चुका है। टीवीके ने महिलाओं को एक लाख रुपए देने और बेटी के ब्याह के लिए आठ ग्राम सोना देने का वादा किया था। यह अब तक का सबसे बड़ा लालच था। इससे पहले टीवी,

फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे महंगे घरेलू उपकरण ही बंटते थे। चुनावी मर्यादा का यह स्पष्ट उल्लंघन है और घोर अलोकतांत्रिक है। मतदाताओं को लालच देकर खरीदने का स्पष्ट उदाहरण है। एक नवोदित क्षेत्रीय पार्टी यकीनन दूसरी क्षेत्रीय पार्टी का विकल्प बन सकती है, लेकिन वह अभी तक किसी राष्ट्रीय दल का पर्याय नहीं बन सकी है। टीवीके शायद डीएमके या एआईडीएमके का विकल्प बन जाए, पर कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी का स्थान लेना उसके लिए आसान नहीं है। भारतीय इतिहास में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कुछ दलों को मिलाकर बनी जनता पार्टी और बाद में जनता दल को एक अवसर मिला था, लेकिन वे जल्द ही बिखर गईं।

इस कड़ी में आम आदमी पार्टी दिल्ली की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में तो उभरी मगर उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार नहीं किया। यही बात राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेडी, अकाली दल, हरियाणा के दल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उत्तरपूर्व के प्रादेशिक दल और वाम दलों पर भी लागू होती है। भारतीय संविधान उन्हें ऐसा करने से रोकता नहीं है।

दरअसल प्रादेशिक पार्टियों ने अपने स्वरूप को राष्ट्रीय स्तर पर विराट रूप देने का प्रयास भी नहीं किया और न ही वे ऐसा करना चाहती थीं। उनका कोई वैचारिक आधार भी नहीं रहा। वे अलग-अलग कालखंडों में तात्कालिक सियासी परिस्थितियों में उत्पन्न हुई थीं। न तो उनके सैद्धांतिक और राष्ट्रीय सरोकार थे और न उनके पास इतने ज्ञानवान राजनेता थे कि वे अखिल भारतीय या अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों को समझते और अपनी पार्टियों को समृद्ध करते।

वे अपनी मूल पार्टियां छोड़कर तो आए मगर उन्होंने जो पार्टियां बनाईं, वे कतई लोकतांत्रिक नहीं थीं। ये नई-नई पार्टियां अपने शिखर नेता के पीछे भीड़ की शक्ल में चलती रहीं और उन्हें राजा या रानी जैसा मानती रहीं। उनमें सामुदायिक नेतृत्व कभी नहीं पनप सका। चाहे वह एमजीआर या करुणानिधि के दल हों या फिर एनसीपी, टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इन क्षेत्रीय पार्टियों ने आंतरिक लोकतंत्र पनपने ही नहीं दिया। वहां वंशवाद की बेल फलती-फूलती रही। उनके नेता कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे। पर उन्होंने नहीं देखा कि राजीव गांधी के बाद जो नेतृत्व आया, वह नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में आया। यह देश उनकी अगुआई में हुए कार्यों का साक्षी है। भारतीय जनता पार्टी में शिखर स्तर पर परिवारवाद नहीं रहा, अलबत्ता क्षेत्रीय स्तर पर अन्य दलों की तरह कुछ कुनबे सामंती शैली में उभरते रहे। प्रादेशिक दलों के लिए यह अत्यंत गंभीर समय है। अब उन्हें अपने सांगठनिक ढांचे की नए सिरे से रचना करनी होगी। उन्हें यह भी समझना होगा कि आज का हिंदुस्तान पचास साल पुराना देश नहीं है, जिसमें कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने और जिंदाबाद-मुर्दाबाद करने का काम करते थे। आज वैश्विक स्तर पर संचार साधनों के नित-नए अवतार आ रहे हैं। इसलिए आज के कार्यकर्ता का केवल भीड़ की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। वह अपनी भूमिका की सार्थकता चाहता है। यह तभी संभव है जब क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपना विस्तार करें, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर गंभीर वैचारिक बहस छेड़ें, भारतीय लोकतंत्र में अपनी पुनर्प्रतिष्ठा करें। लेकिन ऐसा होना कोई आसान काम नहीं है। संभव है कि कुछ समय बाद इन पार्टियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। एक विराट लोकतंत्र में अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव मैदान में रह जाएं तो उसमें भी कोई अनुचित बात नहीं है।

चुनाव परिणामों ने दिखाया नया राजनीतिक ट्रेंड!

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए मिला जुला चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ राज्यों में पार्टी को निराशा हाथ लगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में उसे उल्लेखनीय सफलता भी मिली। इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पक्ष मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहा, जिसने कई राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। खास तौर पर असम और केरलम में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों के मुस्लिम प्रत्याशियों ने प्रभावशाली जीत दर्ज कर यह संकेत दिया है कि इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा अभी भी इस गठबंधन के साथ बना हुआ है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की। राज्य में चुने गए 35 मुस्लिम विधायकों में से 30 संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा से संबंधित हैं। इनमें कांग्रेस के आठ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायक शामिल हैं। यह परिणाम बताता है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर व्यापक भरोसा जताया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उम्मीदवार फातिमा तहलिया की जीत विशेष रूप से चर्चा में रही। उन्होंने कोझिकोड जिले की पेराम्ब्रा सीट पर माकपा नेता टीपी रामकृष्णन को पांच हजार से अधिक मतों से हराया। इस जीत के साथ वह पार्टी की पहली मुस्लिम महिला विधायक बन गईं। उनकी सफलता को मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। असम में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन और भी अधिक प्रभावशाली रहा। पार्टी ने राज्य में 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 18 ने जीत दर्ज की। इसके विपरीत कांग्रेस के अधिकांश गैर मुस्लिम उम्मीदवार हार गए और केवल एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी को सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता दर अत्यंत ऊंची रही। कांग्रेस के सहयोगी रायजोर दल को भी दो सीटों पर जीत मिली, जिनमें एक मुस्लिम उम्मीदवार की थी, जबकि दूसरी सीट अखिल गोगोई ने जीती। अखिल गोगोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा माओवादी गतिविधियों से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है। असम में कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। गौरिपुर सीट पर कांग्रेस के अब्दुल सोबहान अली सरकार ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार निजानुर रहमान को 19097 मतों से हराया। जलेश्वर सीट पर कांग्रेस के आफताब मोल्ला ने एआईयूडीएफ नेता शेख आलम को 109688 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। समागुरी में तंजिल हुसैन ने भाजपा के अनिल सैकिया को 108310 मतों से हराया। इसके अलावा अलगापुर कटलीछड़ा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का अंतर एक लाख से अधिक रहा। इन परिणामों ने यह संकेत दिया कि असम के कई क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से एकजुट हुए। हालांकि असम में कांग्रेस की इस सफलता के बावजूद एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब स्वयं समाप्त हो गई है। अजमल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है और यह स्थिति उन्हें दुखी करती है। उनका यह बयान असम की राजनीति में मुस्लिम मतों को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि चुनाव प्रचार के दौरान असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया था। आखिरकार उनकी बात सही साबित हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर जीत मिली।

‘विजय को मिले बहुमत साबित करने का मौका’

प्रकाश राज ने किया थलापति का समर्थन

थलापति विजय इन दिनों तमिलनाडु चुनावों में अपनी पार्टी 'टीवीके' की जीत को लेकर उत्साहित हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवीके सरकार बनाने के आंकड़े से दूर है। ऐसे में विजय दो बार गवर्नर के पास सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें बहुमत के साथ आने की बात कहकर लौटा दिया है। हालांकि, नियम के मुताबिक, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी सदन में अपना विश्वासमत हासिल कर सकते हैं। अब राज्यपाल द्वारा विजय को बार-बार लौटाने पर अभिनेता प्रकाश राज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने विजय का समर्थन करते हुए गवर्नर पर निशाना साधा है।

जनादेश को स्वीकार करना होगा

एक रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश राज ने कहा कि तमिलनाडु में जनादेश प्राप्त करने के बाद विजय को सरकार बनाने और सदन में अपना बहुमत साबित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, प्रकाश राज ने प्रशासनिक पृष्ठभूमि के बिना नेता के नेतृत्व में शासन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विजय की जीत सत्ता-विरोधी लहर, उनके समर्थकों की लोकप्रियता या सोशल मीडिया की वजह से हुई, इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है। सबसे पहले हमें जनादेश स्वीकार करना होगा।

चुनाव के दौरान उनकी चिंताएं एक नागरिक की थीं, न कि किसी पार्टी कार्यकर्ता की। लोगों को भी गलत होने का अधिकार है, नेताओं को नहीं। शासन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकता और उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि राज्य का संचालन कैसे होगा।

तमिलनाडु के राज्यपाल की कड़ी आलोचना करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि अगर विजय के पास बहुमत है, तो उन्हें दावा पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। विजय के 108 सीटों के समर्थन और कांग्रेस की पांच सीटों के दावे का जिक्र करते हुए अभिनेता ने कहा कि राज्यपाल का घर सच्चाई नहीं है।

इसके अलावा यह सदन का पटल है। राज्यपाल को इस मामले का फैसला सदन में करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें दावा करने दीजिए, उन्हें सदन में साबित करने दीजिए। जनादेश के साथ उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह लोकतंत्र नहीं है, यह वाकई अन्यायपूर्ण है।

विजय के विरोधी भी उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करें

अभिनेता ने कहा कि जो लोग विजय को नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। विजय के पास अब अपने आलोचकों को गलत साबित करने का मौका है। हालांकि, शासन केवल मुख्यमंत्री पर ही नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल और पूरे प्रशासन पर भी निर्भर करेगा।

उन्होंने विजय की पार्टी के वित्त, कृषि, शिक्षा और नौकरशाही के मैनेजमेंट को लेकर रणनीति पर भी सवाल किया। सभी पार्टियां चुनावी वादे करती हैं और उनका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या वे उन वादों के प्रति जवाबदेह हैं।

विजय के साथ राजनीति पर नहीं हुई कभी कोई चर्चा

विजय के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि मैं उनके करियर के पहले दो से ढाई दशकों से उन्हें जानता हूं। कई फिल्मों में उनके साथ काम कर चुका हूं, लेकिन कभी राजनीति पर चर्चा नहीं हुई। यही कारण है कि विजय के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं पर संदेह है। लोकप्रियता ही शासन का आदर्श नहीं हो सकती।चुनाव के दौरान मैंने लोगों से वोट देने से पहले सोचने और यह विचार करने की अपील की थी कि उनके क्षेत्र में कैंडिडेट कौन है। जब पलानीवेल थियागा राजन और स्टालिन जैसे लोग हारते हैं तो चिंता होती है।

कब रिलीज होगा नोरा फतेही का नया गाना?

पोस्टर शेयर करते हुए डांसर ने फैंस से पूछा सवाल

अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही इन दिनों एक विवाद को लेकर चर्चा में हैं। इस विवाद के चलते वह राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं। इस बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उनका नया गाना कब रिलीज होने वाला है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी इसी तरह का एक फोटो शेयर किया है।

नोरा फतेही की पोस्ट में क्या है?

नोरा फतेही ने जो पोस्ट शेयर की है, उसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने मरून ड्रेस में पोज दिया है। ऐसा लगता है कि वह जंगल में हैं। इस पर लिखा है 'बॉडी रोल', नौ मई को रिलीज हो रहा है। इसके साथ नोरा फतेही ने लिखा है 'क्या इस गाने का टीजर आज रिलीज करूं?' इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कई यूजर्स ने मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके गाने का टीजर रिलीज कीजिए।

नोरा को महिला आयोग ने किया तलब

आपको बता दें कि नोरा फतेही मार्च 2026 में उस वक्त चर्चा में आ गई थीं, जब फिल्म 'केडी' का गाना 'सरके चुनर' रिलीज हुआ था। इस गाने पर उन्होंने डांस किया था। इस गाने की दर्शकों ने काफी आलोचना की थी। इसके हिंदी गाने के बोल और विजुअल्स दोनों ही अश्लील और आपत्तिजनक लगे थे। इस मामले पर महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया और नोरा को तलब किया था।

क्या बोली नोरा?

आज नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने बाहर आकर मीडिया से कहा 'यह बस एक ऐसी स्थिति थी जिसमें मुझे डाल दिया गया और मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। एक कलाकार होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। मैंने माफी मांग ली है और सब कुछ लिखित में दे दिया है। वो लोग बहुत ही दयालु और मददगार हैं।'

इन गानों में नजर आईं नोरा

ख्याल रहे कि नोरा फतेही फिल्म 'केडी' में नजर आ चुकी हैं। वह 'थामा' के गाने 'दिलबर की आंखों का' में नजर आ चुकी हैं। वह 'एन एक्शन हीरो' के गाने 'जेडा नशा' और 'सत्यमेव जयते 2' के गाने 'कुसु कुसु' में नजर आ चुकी हैं। वह कई विदेशी कलाकारों के साथ गानों में डांस करते हुए नजर आ चुकी हैं।

राम चरण की 'पेद्दी' के निर्माताओं ने प्रीमियर को लेकर कही यह बात

राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेद्दी' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है। इसी बीच आज निर्माताओं ने फिल्म को लेकर एक अहम जानकारी शेयर की है।

फिल्म को लेकर निर्माताओं ने दिया अपडेट

फिल्म 'पेद्दी' के निर्माताओं ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर घोषणा करते हुए लिखा, PEDDI की एडिटिंग फाइनल हो गई है। 3 जून 2026 को इसका भव्य प्रीमियर होगा और 4 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी।

रत्नवेलु ने की राम चरण की तारीफ

इससे एक हफ्ते पहले फिल्म के कैमरामैन आर. रत्नवेलु ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने राम चरण की तारीफ करते हुए लिखा कि उनके साथ काम करना बहुत खास और यादगार रहा। उन्होंने राम चरण को न सिर्फ अच्छा अभिनेता, बल्कि अच्छा इंसान और दोस्त भी बताया।

फिल्म 'पेद्दी' के बारे में

'पेद्दी' एक ग्रामीण एक्शन ड्रामा फिल्म है। 'पेद्दी' का निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है। इस फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

यह फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

‘वो एनर्जेटिक हैं’, उर्वशी रौतेला ने बताया सेट पर कैसा था नंदमुरी बालकृष्ण का व्यवहार?

तेलुगु सिनेमा के स्टार और नेता नंदमुरी बालकृष्ण फिल्मों के अलावा अपने बयानों और बेबाक स्वभाव को लेकर भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कई बार उनके बयान या व्यवहार विवादों को भी जन्म देते हैं। अब उर्वशी रौतेला ने नंदमुरी बालकृष्ण के साथ अपने कोलैबोरेशन और फिल्म से जुड़े विवादों पर अपनी राय रखी। उन्होंने सेट पर नंदमुरी के व्यवहार और फैंस के साथ उनकी चर्चित बातचीत पर अपना अलग नजरिया रखा।

उनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य

उर्वशी रौतेला ने नंदमुरी बालकृष्ण के साथ ‘डाकू महाराज’ के अपने वायरल गाने और उससे जुड़े विवादों पर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे विवाद शुरू हुआ। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बात दूसरी बात को जन्म देती है, फिर तीसरी, चौथी को, ऐसा ही हुआ था। नंदमुरी बालकृष्ण के साथ काम करना वाकई बहुत ही शानदार था। अगर आप फिल्म देखें, तो हमारे एक्शन सीक्वेंस भी जरूर देखें, वे वाकई कमाल के हैं। उनके साथ काम करने को मेरा सौभाग्य है।

फैंस को पसंद है उनका व्यवहार

नंदमुरी बालकृष्ण अक्सर फैंस के साथ अपने व्यवहार और बातचीत को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस दौरान कई बार वो आक्रामक प्रतिक्रिया देते या फोन फेंकते हुए भी नजर आए। इन वीडियोज को लेकर उर्वशी ने कहा कि मैंने कई बार देखा है और यह हमेशा ऐसा ही होता था। यह सब देखना पहले बहुत मजेदार होता था। फैंस हमेशा नाराज़ नहीं होते। वे भी इसे पसंद करते हैं, वे भी खुश होते हैं।

हंसमुख और सरल स्वभाव के हैं नंदमुरी

नंदमुरी से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए उर्वशी ने बताया कि पिछले साल वैलेंटाइन डे पर बालकृष्ण गारू पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने मुझे विश किया था। एक्ट्रेस ने उन्हें मिलनसार और एनर्जेटिक बताया। बालकृष्ण की कथित गुस्से वाली इमेज को लेकर उर्वशी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गुस्से में ऐसे ही होते हैं। वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और लोगों से खासकर बच्चों से बात करना उन्हें बहुत पसंद है। वो बहुत ही बचकाने और हंसमुख स्वभाव के हैं और जाहिर है कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं।

‘डाकू महाराज’ में नंदमुरी के साथ नजर आई थीं उर्वशी

उर्वशी रौतेला साल 2025 में आई फिल्म ‘डाकू महाराज’ में नंदमुरी बालकृष्ण के साथ नजर आई थीं। यह एक एक्शन-पैक्ड फिल्म थी। फिल्म का गाना ‘दबिड़ि दबिड़ि’ अपने विवादित डांस स्टेप्स को लेकर काफी विवादों में भी रहा था।

तृषा कृष्णन ने शेयर किए थलापति विजय के कई सीक्रेट्स, आप भी रह जाएंगे हैरान

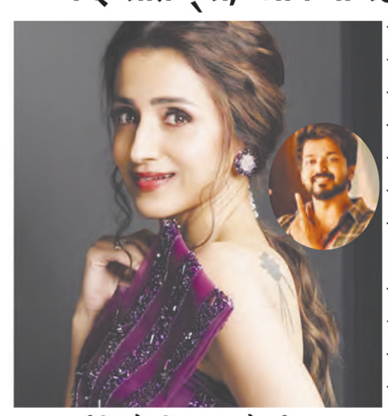

राजनीति में विजय भले ही तूफान ला रहे हों, इसी बीच तृषा कृष्णन का एक पुराना इंटरव्यू फिर से चर्चा में है। इसमें तृषा ने विजय के बारे में ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा।

विजय और तृषा दोनों तमिल सिनेमा की बहुत हिट जोड़ी रहे हैं। उनकी फिल्में जैसे 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' काफी सफल रही हैं। एक चैट शो 'कॉफी विद अनू' में तृषा ने बताया कि शूटिंग के बीच आमतौर पर सभी कलाकार और क्रू मेंबर साथ बैठकर बातें करते और समय बिताते हैं। लेकिन विजय ऐसा नहीं करते थे।

एक पुराने इंटरव्यू में तृषा ने बताया कि विजय सेट पर किसी कोने में चुपचाप बैठ जाते थे। दीवार की तरफ मुंह करके घंटों वहीं रहते थे। वे हमेशा शांत रहते थे और ज्यादा बात नहीं करते थे। दरअसल, विजय ऐसा बिना वजह नहीं करते थे, बल्कि अगले सीन के बारे में सोचते रहते थे।

इस इंटरव्यू में तृषा ने विजय को बहुत अच्छा इंसान बताया। उन्होंने कहा, ''घिल्ली' के समय शुरू में मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि विजय बहुत शांत और रिजर्व स्वभाव के हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए।' तृषा ने आगे कहा, 'मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते या अपना आपा खोते नहीं देखा। वे सेट पर बहुत प्रोफेशनल हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। विजय मेरे लिए हमेशा खास रहेंगे।'

तृषा कृष्णन और थलापति विजय - फोटो : सोशल मीडिया

2023 में दोनों ने 15 साल बाद 'लियो' फिल्म में फिर साथ काम किया। 'लियो' की सफलता इवेंट में तृषा ने कहा, 'विजय के साथ फिर काम करना ठीक वैसा ही लगा जैसे स्कूल के पुराने दोस्त से मिलना। वही अपनापन और प्यार महसूस हुआ। मेरे 20 साल के करियर में सबसे लंबा सफर विजय के साथ रहा है।'

हर फिल्म से जुड़ी याद को इस तरह संभालते हैं प्रभास निजी तौर पर देखते हैं अपना फिल्मी सफर

प्रभास भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उनके बारे में एक नई बात सामने आई है। इससे उनके निजी पहलू के बारे में पता चलता है।

क्या है प्रभास की पुरानी आदत?

प्रभास की एक पुरानी आदत है। वह यह कि वह जिस भी फिल्म में काम करते हैं, उससे जुड़ी कोई एक खास चीज अपने घर ले आते हैं। इसे वह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और करियर के उस दौर की याद के तौर पर रखते हैं।

प्रभास ने अपने पास रखी ये चीजें

सूत्र ने बताया कि यह परंपरा प्रभास के करियर की शुरुआत से ही उनके सफर का हिस्सा रही है। उन्होंने 'रिबेल' से एक कोट, 'बाहुबली' की मशहूर तलवार, 'साहो' से एक बाइक और कार, 'सालार' से उनकी खास बंदूक और 'कल्कि 2898 AD' में इस्तेमाल हुई भविष्य की गाड़ी 'बुज्जी' का एक हिस्सा अपने घर ले गए। उनके लिए ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी यादें हैं जो उन्हें उनके पूरे सफर की याद दिलाती रहेंगी।

अपनी यादों से जुड़े हैं प्रभास

इन वर्षों में, प्रभास ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया है, जिनका लोगों पर गहरा असर पड़ा है। जो चीजें उन्होंने अपने पास रखी हैं, वे उनके इसी सफर को दिखाती हैं।

प्रभास को 'बाहुबली' से जबरदस्त शोहरत मिली है। यह फिल्म दुनियाभर में काफी मशहूर हुई है। इसके बावजूद प्रभास को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जाता है जो अपने काम और उससे जुड़ी यादों से गहराई से जुड़ा रहता है।

फिल्मी सफर को यादगार बनाना चाहते हैं प्रभास

अभिनेताओं का अपनी फिल्मों के कॉस्ट्यूम या चीजें अपने पास रखना कोई नई बात नहीं है। मगर प्रभास जिस तरह हर प्रोजेक्ट में लगातार ऐसा करते हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि वह अपने फिल्मी सफर को कितना यादगार बनाना चाहते हैं और उसे कितने निजी तौर पर देखते हैं।

'द वार्ड' से रियलिटी शो की होस्टिंग में डेब्यू करेंगी रुबीना दिलैक, मातृत्व पर आधारित है शो

मूविंग इमेज स्टूडियोज ने अपने नए नॉन-फिक्शन शो ‘द वार्ड’ की घोषणा कर दी है, जिसे रुबीना दिलैक होस्ट करेंगी। यह एक रियलिटी शो है, जो मां बनने की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाइयों को बहुत सही तरीके से दिखाएगा।

शो में क्या होगा खास?

इस शो में 10 गर्भवती महिलाएं 10 दिनों तक एक छत के नीचे रहेंगी। इस शो को मेटरनिटी वार्ड जैसी सेटिंग में फिल्माया गया है। यह शो, मां बनने की राह पर उनकी असली भावनाओं, विचारों और रिश्तों को ईमानदारी से दिखाएगा। ये महिलाएं अलग-अलग क्षेत्रों से आई हैं। वे धीरे-धीरे अपने निजी अनुभव साझा करेंगी, एक-दूसरे से जुड़ेंगी और बातें करेंगी। इन बातों में शामिल होंगे- समाज की उम्मीदें, लड़कियों के प्रति भेदभाव, करियर की चाहत, परिवार में बदलते रिश्ते और मां बनने की चुनौतियां। रुबीना दिलैक सिर्फ होस्ट नहीं हैं, बल्कि वे सहानुभूति और समझ के साथ इन महिलाओं से जुड़ेंगी। खुद नई मां होने के नाते वे अपने अनुभव भी साझा करेंगी और सभी को सहारा देंगी। यह शो 15 मई को यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा।

प्रतिभागियों के पति और परिवार वाले भी इस सफर का हिस्सा बनेंगे। वे साथ रहकर सीखेंगे, समझेंगे और रिश्तों को मजबूत करेंगे। शो में 24 घंटे कैमरा, डॉक्टरों की देखभाल और गहरी कहानी सुनाई जाएगी। इससे मातृत्व के सच्चे, कच्चे और दिल को छूने वाले पलों को दिखाया जाएगा।

शो को लेकर रुबीना दिलैक की राय

रुबीना ने अपने सोशल मीडिया पर शो का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'मां बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा और भावनात्मक सफर रहा है। यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना मुश्किल भी कि कोई आपको पहले से तैयार नहीं कर सकता। ‘द वार्ड’ उन अनकही भावनाओं को दिखाता है, जिन्हें हम अंदर ही दबा लेते हैं। यह मेरा पहला रियलिटी शो है और मैं कह सकती हूं कि यह हर किसी के लिए भावनाओं का रोलरकोस्टर होगा।'

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कांग्रेस-टीवीके गठबंधन से अवसरवाद की बू आती है

नईदिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के साथ गठबंधन करने के कांग्रेस के फैसले को शुक्रवार को बहुत खराब करार दिया और कहा कि इससे निम्न स्तर के राजनीतिक अवसरवाद की बू आती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर जोर भी दिया कि अगर यह कदम द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व वाले राज्य में सांप्रदायिक भाजपा के पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है तो यह सबसे खतरनाक और राजनीतिक फुटबॉल के इतिहास में सबसे खराब आत्मघाती गोल साबित होगा। अय्यर ने कहा कि वह इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि कांग्रेस के पूर्वज ऐसी अवसरवाद की राजनीति को अपना आशीर्वाद देते। उन्होंने मीडिया- से कहा कि द्रमुक के साथ चुनाव लड़ने के तुरंत बाद उस टीवीके के साथ गठजोड़ करने का फैसला बहुत खराब है, जिसने 23 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराया।''

संजय राउत ने डोनाल्ड ट्रम्प को लिखा पत्र

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर बधाई संदेशों की खबरों के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखे अपने ट्वीट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि उनका मानना है कि चुनाव को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाई जा रही चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखना उनका कर्तव्य है। राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि यह खबर झूठी है। अगर कल मोदी ग्राम पंचायत चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप, मैक्रॉन और स्टारमर मोदी को बधाई देंगे? अमेरिका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत भी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ने बार-बार इस पर अपनी राय रखी है।

भारतीय राजनीति के जोकर राउत पर भाजपा का हमला

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित सोशल मीडिया पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने राउत को भारतीय राजनीति का जोकर बताते हुए उन पर भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संजय राउत भारतीय राजनीति के जोकर हैं। वह और राहुल गांधी घरेलू राजनीतिक लड़ाई के लिए भारत की छवि खराब करने की सुपारी लेकर बैठे हैं। मोदी विरोध में ये लोग देश का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र की सराहना हो रही है, लेकिन विपक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर झूठे नैरेटिव फैलाने में जुटा है। पूनावाला ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और खबरों के मुताबिक ट्रंप ने भी भाजपा को बधाई दी है।

अखिलेश ने कांग्रेस को घेरा हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके से संबंध तोड़ने और अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को राज्य में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। एक्स पर एक तीखे संदेश में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, मुश्किल समय में हम एक-दूसरे का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, जो तमिलनाडु में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कांग्रेस पर एक स्पष्ट कटाक्ष था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और विधानसभा त्रिशंकु हो गई। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बाद में उसने पांच विधायकों वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला किया।

चिदंबरम ने तमिलनाडु गवर्नर को याद दिलाया सुको का फैसला

नईदिल्ली। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन या राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल का क्या कर्तव्य है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक नियम है। यह संसदीय परंपरा है। राज्यपाल द्वारा विजय को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किए जाने की ओर इशारा करते हुए चिदंबरम ने कहा, विधानसभा - न कि राज्यपाल का आवास - उस पार्टी के नेता के लिए यह साबित करने का उचित मंच है कि उसे बहुमत प्राप्त है। यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है: 1994 (3) एससीसी 1।

केरल मुख्यमंत्री की रेस में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे

63 में से 47 विधायकों का मिला समर्थन

तिरुवनंतपुरम। एआईसीसी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को एआईसीसी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हुई व्यक्तिगत बैठकों के दौरान कांग्रेस के 63 निर्वाचित विधायकों में से 47 ने, जिनमें केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ भी शामिल हैं, केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। पार्टी उच्च कमान द्वारा इस सप्ताह के अंत तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए जाने की संभावना है। सनी के अलावा, संदीप जी वेरियर, सजीव जोसेफ, टी ओ मोहन और उषा विजयन सहित अन्य नवनिर्वाचित विधायकों ने वेणुगोपाल का नाम प्रस्तावित किया। शीर्ष पद के एक अन्य दावेदार रमेश चेन्निथला को करारा झटका लगा जब उनके करीबी आई सी बालकृष्णन ने वेणुगोपाल और चेन्निथला दोनों का समर्थन किया। सूत्रों के अनुसार, पूर्व विपक्ष नेता को आठ नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मौजूदा विपक्ष नेता वी डी सतीशान, जिन्हें इस पद के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार माना जा रहा है, को छह विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सतीशान और चेन्निथला दोनों ने भी पर्यवेक्षकों से मुलाकात की और पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। वेणुगोपाल बैठक में अनुपस्थित रहे।

63 विधायकों के अलावा, माकन और वासनिक ने कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत बैठकें करके उनकी राय जानने की कोशिश की। जहां तीन पूर्व केपीसीसी अध्यक्षों ने सतीशान का समर्थन किया, वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने वेणुगोपाल का साथ दिया। नई दिल्ली लौट चुके पर्यवेक्षक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सूत्रों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर हाई कमांड सनी, तीनों केपीसीसी कार्यकारी अध्यक्षों के साथ-साथ सतीशान और चेन्निथला को भी बातचीत के लिए बुलाएगा।

इसी बीच, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से खरगे को अगले मुख्यमंत्री को नामित करने का अधिकार दे दिया गया। सूत्रों ने बताया कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उच्च कमान शनिवार या रविवार तक अगले मुख्यमंत्री की घोषणा कर देगा और नए मुख्यमंत्री, दो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और यूडीएफ के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ, घोषणा के दो दिनों के भीतर शपथ लेंगे।

पर्यवेक्षकों ने खरगे को सौंपी रिपोर्ट

कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरल के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी है। इसी बीच, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के समर्थक सड़कों और सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त अजय माकन ने कहा, शुक्रवार को हमने कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। नवनिर्वाचित विधायक दलकी बैठक ने एक-लाइन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया और उस प्रस्ताव की एक प्रति भी सौंप दी गई। हमने विधायकों से एक-एक करके बात की और उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे नोट कर लिया। सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि कई लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। हमने उसे नोट कर लिया है और हाई कमान को सौंप दिया है।

मणिकम टैगोर का भाजपा पर बड़ा हमला

अमित शाह के कंट्रोल में है तमिलनाडु की पूरी पॉलिटिक्स: कांग्रेस

चेन्नई। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को भाजपा की आलोचना करते हुए उस पर राज्य में तेजी से और अप्रत्याशित घटनाक्रमों के बीच तमिलनाडु की राजनीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अचानक अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं। तमिलनाडु अब नीतीश कुमार के प्रभाव वाला तमिलनाडु बन गया है। भाजपा ने तमिलनाडु पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया है और जो लोग कहते थे कि हम नियंत्रण से बाहर हैं, वे खुद भाजपा के नियंत्रण में आ गए हैं। एआईएडीएमके ने आत्मसमर्पण कर दिया है और डीएमके पर भाजपा का कब्जा हो गया है।

टैगोर ने आगे कहा कि तमिलनाडु में एनडीए नहीं है क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ एक विधायक है। भाजपा, खासकर अमित शाह, किसी भी कीमत पर विजय कुमार को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। विदुथलाई चिरुथाइगल कच्ची (वीसीके) और वामपंथी दलों को संबोधित करते हुए टैगोर ने गठबंधन सहयोगियों से भाजपा के रणनीतिक इरादों को समझने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे भाजपा की योजना को गलत नहीं समझेंगे। सभी वामपंथी दलों और वीसीके के मित्रों को यह समझना चाहिए। और आईयूएमएल को भी यह समझना चाहिए कि एआईएडीएमके और डीएमके के साथ गठबंधन श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ही हो रहा है।

टैगोर ने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें और श्री अमित शाह की योजनाओं को नकार दिया है। डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन तमिलनाडु के लिए बेहद विनाशकारी होगा। इसी बीच, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने विजय से समर्थन वापस लेने पर विचार करने के लिए अलग-अलग कार्यकारी बैठकें बुलाईं। दोनों पार्टियों के पास दो-दो विधायक हैं। उनके समर्थन से टीवीके गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़कर 117 हो जाएगी, जो 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से मात्र एक कम है।

बाद में दिन में, वामपंथी दलों ने टीवीके के समर्थन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए वीसीके के नेताओं से मिलने की योजना बनाई, जिसने चुनाव में दो सीटें जीती थीं। टीवीके को अपनी पार्टी के संभावित समर्थन के बारे में पूछे जाने पर, वीसीके प्रमुख थोल. थिरुमावलवन ने कहा कि पार्टी अपने उच्च स्तरीय समिति सदस्यों और वामपंथी दलों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लेगी। थिरुमावलवन ने कहा कि आज हमारी अपने उच्च स्तरीय समिति सदस्यों के साथ बैठक है। हम इस मौजूदा राजनीतिक संकट पर चर्चा करने जा रहे हैं, और हम वामपंथी दलों के निर्णयों के बाद निर्णय लेंगे। हम उनके निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही मेरा संदेश है।

लोकसभा में बदलेगा डीएमके सांसदों का स्थान?

कांग्रेस से दूरी के बाद स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने लोकसभा में अपने सांसदों की सीट व्यवस्था बदलने की मांग उठाई है। पार्टी ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने अपने पत्र में कहा है कि कांग्रेस के साथ पार्टी का राजनीतिक गठबंधन समाप्त हो चुका है। ऐसे में संसद के भीतर डीएमके सांसदों का कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना अब मौजूदा परिस्थितियों में उचित नहीं माना जा सकता।

तमिलनाडु की राजनीति में हाल के दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में आई खटास अब संसद तक पहुंचती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीटिंग व्यवस्था बदलने की मांग केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि गठबंधन टूटने का सार्वजनिक संकेत भी है। सूत्रों के अनुसार, डीएमके चाहती है कि उसके सांसदों को लोकसभा में अलग ब्लॉक में सीट आवंटित की जाए ताकि पार्टी की नई राजनीतिक स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।

लोकसभा में सीट व्यवस्था केवल बैठने का मामला नहीं होता, बल्कि यह राजनीतिक समीकरणों और दलों के रिश्तों का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में डीएमके का यह कदम राष्ट्रीय राजनीति में नए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, इस मामले में लोकसभा सचिवालय या स्पीकर कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन डीएमके के इस पत्र ने संसद के आगामी सत्र से पहले राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है।

खेल

प्रमुख समाचार

राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला आज

जयपुर। आत्मविश्वास से ओतप्रोत गुजरात टाइटन्स शनिवार को यहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात की टीम की स्थिति लगभग समान है। इन दोनों ने अब तक 10 मैचों में छह जीत और चार हार दर्ज की हैं। रॉयल्स बेहतर नेट रन रेट (0.510) के कारण गुजरात से आगे है। गुजरात टाइटन्स ने हालांकि लगातार तीन जीत हासिल की हैं और वह शीर्ष चार में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। आईपीएल का मौजूदा सत्र गेंदबाजों के लिए अच्छा नहीं रहा है और ऐसे में रॉयल्स को विशेष कर बीच के ओवरों में अपनी गेंदबाजी की समस्याओं को दूर करना होगा। गुजरात टाइटंस की टीम इस बात से खुश होगी कि उसने सही समय पर लय हासिल कर ली है। कप्तान शुभमन गिल (378 रन) के प्रदर्शन में निरंतरता है और वह इसे बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। साई सुदर्शन (385) भी अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। उन्होंने अपनी पिछली चार पारियों में दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है। जोस बटलर (335) के निरंतरता बनाए रखने से गुजरात टाइटन्स का शीर्ष क्रम बेहद मजबूत नजर आता है। उसके पास निचले क्रम में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में माहिर अच्छे फिनिशर भी हैं। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी भी अच्छी है। कैगिसो रबाडा (16 विकेट) तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई बखूबी कर रहे हैं। उसकी टीम रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा (12) और मोहम्मद सिराज (11) की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के प्रदर्शन से काफी खुश होगी। यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में 220 से अधिक के स्कोर का दो बार सफलतापूर्वक पीछा किया जा चुका है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 516 अंक टूटा निफ्टी 24,176 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट लेकर लाल निशान पर बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 516 अंक फिसल गया, जबकि निफ्टी-50 150 अंक टूटकर 24,176 पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर घरेलू बाजार पर देखने को मिला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 77,631 के स्तर पर खुला। दिन के कारोबार के दौरान इस इंडेक्स ने 77,647.44 के हाई और 77,146.43 के लो रेंज में ट्रेड किया। अंत में सेंसेक्स 516.33 अंक यानी 0.66% फिसलकर 77,328.19 पर बंद हुआ। इसी तरह, 50 शेयरों वाले निफ्टी-50 की शुरुआत 24,233 के स्तर पर हुई। दिन के कारोबार के दौरान इस इंडेक्स ने 24,253.80 के हाई और 24,126.65 के लो रेंज में ट्रेड किया। अंत में निफ्टी-50 150.50 अंक यानी 0.62% टूटकर 24,176.15 पर बंद हुआ।

सिलेंडर के लिए ओटीपी सिस्टम बना परेशानी की वजह

मुंबई। ईरान-इजरायल तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर वैश्विक चिंताओं के माहौल में भारत में एलपीजी सिलेंडर वितरण व्यवस्था को लेकर नया विवाद सामने आया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लागू किए गए ओटीपी आधारित डिजिटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लेकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और ऑफलाइन बुकिंग व डिलीवरी विकल्पों की निरंतरता पर विचार करें। बता दें नए नियमों के तहत 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

अमेरिकी अदालत ने 10% ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

वाशिंगटन। अमेरिका की एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए उसके लागू करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के आर्थिक एजेंडे के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे कुछ ही महीने पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए पहले के कुछ टैरिफ को भी रद्द कर दिया था। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक, मैनहट्टन स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में तीन जजों की डिविजन बेंच ने गुरुवार को छोटे व्यवसायों के एक समूह और ज्यादातर डेमोक्रेट शासित दो दर्जन राज्यों की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें इन टैरिफ को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। ट्रंप ने फरवरी में 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत शुल्क लगाया था। इस धारा का पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था।

पराग मिल्क फूड्स का चौथी तिमाही में लाभ 23.31% बढ़ा

नई दिल्ली। पराग मिल्क फूड्स का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 23.31 प्रतिशत बढ़कर 40.14 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में शुद्ध मुनाफा 32.55 करोड़ रुपए था। पराग मिल्क फूड्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़कर 945.34 करोड़ रुपए हो गई जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 918.25 करोड़ रुपए थी। खर्च भी 898.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 924.06 करोड़ रुपए हो गया। समूचे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ 152.39 करोड़ रुपए रहा जो 2024-25 के 132.59 करोड़ रुपए से 15 प्रतिशत अधिक है। इन्होंने 2025-26 की चौथी तिमाही में 100 करोड़ रुपए के तिमाही राजस्व का आंकड़ा पार किया।

'दृष्टि' के जरिये भारत के नये अंतरिक्ष युग की शुरुआत

पीके जोशी

भारतीय स्टार्टअप अब तेजी से उन्नत अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट में भारतीय स्टार्टअप, गैलेक्सआइ द्वारा एक खास उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाना इस नवपरिवर्तन को दिखाता है। इसका नाम है 'दृष्टि'। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि दिखाती है कि अब अंतरिक्ष क्षेत्र सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं द्वारा शुरू किये गये स्टार्टअप इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों ने जो मजबूत नींव तैयार की, उस पर निजी कंपनियां नयी ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं।

इसकी महत्ता को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि पारंपरिक उपग्रह संवेदक कैसे काम करते हैं। आमतौर पर उपग्रह संवेदक दो प्रकार की तकनीक पर आधारित होते हैं- ऑप्टिकल (प्रकाशीय संवेदक) और सिंथेटिक (कृत्रिम) अपर्चर रडार (एसएआर)। ऑप्टिकल संवेदक बिल्कुल सामान्य कैमरे की तरह काम करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के आधार पर तस्वीरें लेते हैं, जिससे स्पष्ट और समझने में आसान चित्र प्राप्त होते हैं। पर इनकी एक सीमा है- ये बादल, धुएं या सूर्य के प्रकाश के अभाव में काम नहीं कर पाते। दूसरी ओर एसएआर तकनीक, माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग करती है, जो बादलों और धुएं को आसानी से पार कर सकते हैं, और अंधेरे में भी काम करते हैं। इससे हर समय, हर मौसम में निगरानी करना संभव हो जाता है। हालांकि, एसएआर से मिलने वाली तस्वीरें सामान्य चित्र जैसी नहीं होतीं, बल्कि एक्स-रे जैसी जटिल होती हैं, जिन्हें समझने के

लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है।

'दृष्टि' को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें इन दोनों तकनीकों को एक ही उपग्रह में जोड़ा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि दोनों संवेदक एक ही समय पर एक ही स्थान की तस्वीर लेने के लिए पूरी तरह समन्वित हैं। इस तकनीक को गैलेक्सआइ ने 'ऑप्टोएसएआर' नाम दिया है। पहले ऑप्टिकल और एसएआर के संलयन के लिए विभिन्न उपग्रहों और विभिन्न समयों से प्राप्त चित्र लेने पड़ते थे, जिससे अक्सर अध्ययन में असंगति आ जाती थी। 'दृष्टि' इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम है। अब यदि बादलों या अंधेरे के कारण ऑप्टिकल संवेदक काम नहीं कर पाता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एसएआर डाटा से ऑप्टिकल जैसे चित्र तैयार किये जा सकते हैं।

'दृष्टि' को बनाना आसान नहीं था। ऑप्टिकल और एसएआर सेंसर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं तथा पृथ्वी को अलग-अलग कोण से देखते हैं। यदि इनमें ठीक से तालमेल न किया जाये, तो ये अलग-अलग स्थानों की तस्वीरें ले सकते हैं। गैलेक्सआइ ने अपनी विशेष तकनीक के जरिये इस समस्या को हल किया और दोनों संवेदकों को एक साथ काम करने के लिए तैयार किया। इससे हर समय उपयोगी चित्र उपलब्ध रहेंगे। यह सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, व्यावहारिक बदलाव भी है, क्योंकि इससे उपग्रहीय आंकड़े अब अधिक लोगों के लिए उपयोगी और सुलभ हो जायेंगे। इस उपलब्धि को भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के संदर्भ में समझना भी जरूरी है। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉसमॉस और हैदराबाद स्थित स्काइरूट एयरोस्पेस जैसे स्टार्टअप पहले ही थ्रीडी प्रिंटेड रॉकेट इंजन और निजी रॉकेट लॉन्च जैसी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वहीं पिक्सेल (नयी दिल्ली), ध्रुवा स्पेस (हैदराबाद) और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस (बेंगलुरु) जैसी कंपनियां उपग्रह और प्रणोदन तकनीकों में नये प्रयोग कर रही हैं। ये सभी मिलकर भारत में एक मजबूत और तेजी से विकसित हो रहा अंतरिक्ष बाजार बना रहे हैं। 'दृष्टि' की उपयोगिता भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां अक्सर बादल छाये रहते हैं, खासकर मॉनसून के दौरान, जिससे ऑप्टिकल छायाचित्रण में बाधा आती है।

भाजपा का संगठन सुदृढ़ीकरण पर जोर

बूथ से लेकर जिला तक कार्ययोजना तय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला की आवश्यक बैठक आज जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित की गई।

बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत आयोजित होने वाले जिला प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा एवं मंडल, शक्ति केंद्र तथा बूथ स्तर पर नियमित बैठकों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम, समर्पण और जीवटता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी और अंततः विजय प्राप्त की। श्री कश्यप ने बस्तर क्षेत्र के उदाहरण देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी संगठन की ताकत से बड़े परिवर्तन संभव हैं।

बैठक में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी एवं रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, नियमित बैठकों के आयोजन और मन की बात कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया।

बैठक में प्रदेश कार्यालय मंत्री एवं जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी अशोक बजाज ने 23 एवं 24 मई को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी अपेक्षित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य बताई। जिला संगठन प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब संगठनात्मक कार्यों को योजनाबद्ध, समयबद्ध एवं परिणाममुखी तरीके से करना होगा। मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर पर नियमित बैठक, रजिस्टर संधारण, एजेंडा आधारित कार्यवाही एवं समीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने पर उन्होंने बल दिया। जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ में निहित है। उन्होंने बताया कि जिले में बूथों की संख्या बढ़कर 1479 हो गई है, ऐसे में प्रत्येक बूथ पर 25 सदस्यीय सशक्त समिति का गठन, पूर्व समितियों का शुद्धिकरण एवं नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर पर प्रत्येक माह नियमित बैठक, मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण तथा सभी बैठकों का रजिस्टर संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन जिला महामंत्री अमित शाह मैशेरी ने किया।

मानव सेवा ही रेडक्रॉस की असली पहचानः गजेंद्र यादव

रायपुर। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज रायपुर के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने सेवा और मानवता के क्षेत्र में सक्रिय रेडक्रॉस काउंसलरों और स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि निःस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्व रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में जूनियर एवं यूथ रेडक्रॉस सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित लोक नृत्य, चित्रकला और नाट्य प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को मंत्री महोदय ने पुरस्कृत किया। प्रदेश के कुल 64 रेडक्रॉस वॉलिंटियर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

समाजसेवियों और अधिकारियों को किया सम्मानित

समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने समाजसेवियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अंगदान, रक्तदान, नेत्रदान और देहदान जैसे पुनीत कार्यों के जरिए समाज में नई चेतना जागृत की है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की त्वरित सहायता करना और जरूरतमंदों तक सेवा पहुँचाना रेडक्रॉस परिवार की अद्भुत कार्यसंस्कृति को दर्शाता है। श्री रामसिंह अग्रवाल सदस्यता एवं समाज सेवा के लिए, श्री सूरज साहू रक्तदान के लिए, कमलेश निषाद सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए, पवन गांधी और आकांक्षा श्रीवास्तव नेत्रदान, नेत्रदान, अंगदान एवं देहदान के लिए सम्मानित किया गया। मंत्री श्री यादव ने सभी से करुणा और सहयोग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री यादव ने कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न जिलों के कलेक्टरों (को सम्मानित किया गया। इनमें डॉ. गौरव कुमार सिंह, अभिजीत सिंह, एस. जयवर्धन, डॉ. संजय कन्नौजे, रोहित व्यास, दिव्या उमेश मिश्रा, अविनाश मिश्रा एवं कुणाल दुदावत के प्रतिनिधि शामिल रहे। इसके अतिरिक्त, मानवता की विशिष्ट सेवा हेतु व्यक्तिगत रूप से भी कई स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया गया।

सरकार जनआस्था से जुड़े स्थलों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध : अग्रवाल

रायपुर। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार जनआस्था से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक-सांस्कृतिक अधोसंरचना के विकास के लिए निरंतर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 में शनि मंदिर तालाब के सौंदर्यीकरण एवं छठ घाट निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्र की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जनसुविधाओं को नई दिशा देने वाला साबित होगा। लगभग 34 लाख रुपये की लागत से किए जाने वाले इस कार्य के अंतर्गत शनि मंदिर तालाब का सौंदर्यीकरण, परिसर का व्यवस्थित विकास तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधायुक्त छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक आयोजनों एवं पर्वों के दौरान लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि क्षेत्र की स्वच्छता, सौंदर्य एवं सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक स्थल केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं होते, बल्कि समाज को जोडने, संस्कृति को जीवित रखने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम भी होते हैं।

मुख्यमंत्री से भारतीय रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ शाखा के चेयरमेन श्री तोमन साहू जी चेयरमेन एवं अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को रेडक्रॉस का बैज पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर विश्व रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता की सेवा के साथ ही आपदा के समय में रेडक्रॉस संस्था की भूमिका सराहनीय है।इस अवसर पर वाइस चेयरमेन श्री रुपेश पाणिग्रही,कोषाध्यक्ष श्री संजय पटेल,राज्य प्रबंध समिति सदस्य श्री प्रदीप साहू, संरक्षक सदस्य श्री दिनेश तापड़िया उपस्थित थे।

रोक्तिमा यादव को कोरिया कलेक्टर की कमान,पुष्पा साहू माशिमं की सचिव

रायपुर। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल करते हुए नई नियुक्तियां जारी की हैं। इस आदेश के तहत शिक्षा और जिला स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2012 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री पुष्पा साहू को सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि 6 मई 2026 को जारी आदेश के तहत सुश्री पुष्पा साहू को कलेक्टर जिला-कोरिया पदस्थ किया गया था, जिसमें जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ किया गया है।

वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव को जिला-कोरिया का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वे आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। 6 मई 2026 को जारी आदेश के तहत श्रीमती रोक्तिमा यादव, द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधित करते हुए कलेक्टर जिला-कोरिया पदस्थ किया गया है।

वर्ष 2019 बैच की आईएएस अधिकारी श्रीमती रीता यादव को आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उनके पदभार संभालते ही इस पद को वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जाएगा।

नए आदेश के बाद तीनों अधिकारी जल्द ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। कोरिया जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद रोक्तिमा यादव स्थानीय प्रशासन की समीक्षा बैठक ले सकती हैं, वहीं शिक्षा विभाग में नए अधिकारियों के आने से आगामी परीक्षाओं और शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सुशासन नहीं केवल आवेदन तिहारः बैज

रायपुर। तथाकथित सुशासन असली पोल सुशासन त्यौहार में खुल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मंत्री, विधायक, सांसद अब अधिकारियों को धमकाने, चमकाने पर उतर आये है। ढाई साल के सरकार जनता से दूर हो चुकी है। सुशासन त्यौहार के नाम पर जब जनता के बीच जा रहे तब जनाक्रोश को दबाने अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे है। मंत्री दयालदास बघेल मंच से शराब तस्करी के लिए पुलिस को दोषी ठहरा रहे है, तो विधायक रोहित साहू पटवारी को धमका रहे है, सांसद भोजराज नाग अधिकारी को निपटाने की धमकी दे रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ महिलाओं से महतारी वंदन का फार्म भरवाये, 18 लाख पीएम आवास देने का फर्जी दावा किये, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का झूठा वादा किये, अब उस वादाखिलाफी से ध्यान भटकाने सुशासन तिहार के नाम पर एक बार फिर आवेदन जमा किये जा रहे है, सरकार का फोकस समस्या के निराकरण में नहीं है। पेयजल व्यवस्था बदहाल है, बूंद-बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है, मनरेगा के श्रमिक काम के इंतजार में खाली बैठे हैं, शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई है।

कटौती और महंगी बिजली से जनता परेशान : शुक्ला

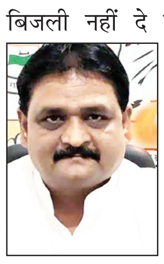

रायपुर। मई माह में 45 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल औसत से दुगुना आया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिजली बिल सरकार प्रायोजित लूट है। जनता बढ़े बिजली बिल से परेशान हो गयी है। भाजपा सरकार जनता को राहत देने के बजाय जनता को लूटने में लगी है। जनता बिजली कटौती से परेशान है। सरकार 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही उपर से अनाप-शनाप बिजली बिल भेज रही है। बिजली के बढ़े बिल से पिछले 6 माह से जनता पर बोझ डाला जा रहा था लेकिन इस माह बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है। औसतन हर उपभोक्ता का बिजली बिल दुगुना आया है। बिजली बिल ज्यादा आने का तीन कारण है। दूसरा बिजली बिल हाफ योजना बंद हो गई। तीसरा स्मार्ट मीटर लगाए गए है जो अनाप शनाप खपत से अधिक रीडिंग बता रहा जिससे बिल अधिक आ रहा। मई माह में लोगों का बिजली बिल दुगुना आया है, बढ़े बिजली बिल से जनता परेशान है। सरकार प्रायोजित लूट है बढ़े हुए बिजली बिल भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण छत्तीसगढ़ की जनता का महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है।

ताड़मेटला कांड : परिजनों को न्याय नहीं दिला पायीः ठाकुर

रायपुर। ताड़मेटला कांड के पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने के लिए राज्य सरकार एवं जांच एजेंसियों को दोषी ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार एवं जांच एजेंसियों के नाकामी के चलते ताड़मेटला कांड में जवानों के शहादत के लिए जिम्मेदार कथित 7 आरोपी बरी हो गये। शहीदों के परिजनों को न्याय दिलाने में सरकार असफल साबित हो गई है। ताड़मेटला कांड में शामिल आरोपी ओयमी गंगा, मांडवी दुला, पोदयामि हिड़मा, ओयमी हिड़मा, कवासी बुथरा सहित 7 आरोपी थे, जिन्हें कोर्ट सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। सरकार बताये कि यदि ये गुनाहगार नहीं तो असली गुनाहगार कौन है? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की तत्कालीन सरकार ने निर्दोष आदिवासियों को बलि का बकरा बनाया था और मुख्य आरोपी को बचाया था। ताड़मेटला कांड में हमारे 76 जवान शहीद हुए थे, 75 जवान सीआरपीएफ के थे एक जवान राज्य पुलिस से। कांग्रेस ने पहले ही मांग की थी कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। कांग्रेस के दबाव में कुछ निर्दोष आरोपियों को पकड़कर लीपापोती किया था। यह स्थिति झीरम एवं एडसमेटा में हुई सरकार आज तक वास्तविक आरोपियों को पकड़ नहीं पायी है।

लोकभवन में लगा मेगा हेल्थ कैंप

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका के मार्गदर्शन में आज लोकभवन में व्यापक चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर विशेष रूप से महिलाओं के लिये आयोजित किया गया। शिविर में सामान्य बीमारियों के साथ-साथ हृदय रोग, कैंसर, किडनी, स्त्री रोग और अन्य गंभीर बीमारियों की निशुल्क जांच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। विशेष रूप से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए स्क्रीनिंग भी की गई।लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में जिला प्रशासन रायपुर के 'प्रोजेक्ट छांव' के अंतर्गत आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 300 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान व्ही वाय हॉस्पिटल के मोबाइल कैंसर डिडक्शन यूनिट द्वारा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रेडक्रॉस ब्लड बैंक की मोबाइल यूनिट उपलब्ध रही।शिविर में विभिन्न शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर की टीम द्वारा लैब जांच, बीपी और शुगर जांच की गई। वहीं एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट एंड आईवीएफ रिसर्च सेंटर द्वारा हृदय रोग परामर्श, ईसीजी एवं ईको जांच की सुविधा दी गई।

मुख्यमंत्री बनने पर सुभेंदु अधिकारी को देव ने दी बधाई

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने श्री सुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं। श्री देव ने अपने बधाई संदेश में कहा कि अधिकारी का नेतृत्व पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जन-आकांक्षाओं को स्वर देने में मील का पत्थर साबित होगा और अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में बंगाल भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अखण्ड भारत के स्वप्नद्रष्टा अमर बलिदानी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों के 'सोनार बांग्ला' के संकल्प को सिद्ध करने के लिए नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। देव ने देव ने कामना की कि भाजपा शासनकाल बंगाल में भयमुक्त वातावरण का सृजन करके राज्य को नवनिर्माण की ओर अग्रसर करेगा। बंगाल की जनता जिस सुशासन और सर्वतोमुखी विकास की प्रतीक्षा कर रही है, उसे धरातल पर उतारने में श्री अधिकारी के नेतृत्व में गठित होने वाली प्रदेश सरकार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत

वैदिक मंत्रोच्चार से 62 जोड़ों का विवाह संपन्न

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देशानुसार रायपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत आज तीन विभिन्न स्थलों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कुल 62 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ नए जीवन की शुरुआत की।

टाऊन हॉल, आरंग में 16 जोड़ों का विवाह कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री गुरू खुशवंत साहेब के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन, जनपद अध्यक्ष टाकेश्वरी मुरली साहू, जनपद सदस्य पद्मिनी साहू एवं जनपद उपाध्यक्ष श्री रविन्द्र चंद्राकर उपस्थित रहे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन, सासाहोली, तिल्दा-नेवरा में 31 जोड़ों का विवाह जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जनपद पंचायत अध्यक्ष टीकेश्वर मनहरे, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा, जिला पंचायत सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास सभापति शैल महेन्द्र साहू, जनपद सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास सभापति सरोज मुकेश भारद्वाज, नगर पालिका उपाध्यक्ष पलक सुखवानी एवं समस्त पार्षदगण तिल्दा की उपस्थिति में संपन्न कराया गया।

मंगल भवन, धरसीवां में 15 जोड़ों का विवाह जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सरोज चंद्रवंशी एवं जनपद अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला सेन की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।शासन द्वारा सभी नवविवाहित जोड़ों को योजनांतर्गत निर्धारित सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नवदंपत्तियों को सुखमय एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन हेतु शुभकामनाएं दीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बेटियों का सम्मान और सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से गरीब परिवारों को संबल मिल रहा है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल रहा है।इस दौरान विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से बचाव हेतु सिम्स का वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) द्वारा हेपेटाइटिस बी एवं सी जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक जागरूकता एवं वैक्सीनेशन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ तथा विद्यार्थियों को हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण, उसके फैलने के तरीके, लक्षण, संभावित खतरे तथा बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार हेपेटाइटिस एक गंभीर संक्रमणजनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से लीवर (यकृत) को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित सुई, असुरक्षित रक्त चढ़ाने, संक्रमित उपकरणों के उपयोग तथा संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रवों के संपर्क से फैल सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं नर्सिंग स्टाफ में इसका खतरा अधिक रहता है, क्योंकि वे नियमित रूप से मरीजों के संपर्क में रहते हैं।

चिकित्सकों ने बताया कि हेपेटाइटिस संक्रमण प्रारंभिक अवस्था में सामान्य कमजोरी, भूख कम लगना, उल्टी, बुखार, थकान, पेट दर्द तथा आंखों और त्वचा के पीले पडने् जैसे लक्षणों के रूप में दिखाई दे सकता है। कई बार यह बीमारी लंबे समय तक बिना लक्षण के भी शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है और बाद में लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.